20 जनवरी, 2022 * वर्ष 31, पृष्ठ संख्या, 60, अंक-1

राजस्थान सुजस

नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ

जरूरतमंदों को बांटे कम्बल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नव वर्ष के अवसर पर रामनिवास बाग के पीछे बने नगर निगम के अस्थायी रैन बसेरे में जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए।

श्री गहलोत ने रैन बसेरे में मौजूद लोगों से बड़ी आत्मीयता से बात की और उनके हालचाल पूछे। उन्होंने उपचार के लिए जयपुर आए और रैन बसेरे में रह रहे उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के रोगियों एवं उनके परिजनों से बातचीत की। रोगियों एवं उनके परिजनों ने बताया कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं। वे यहां मिले उपचार से संतुष्ट हैं। साथ ही प्रदेश के कुछ रोगियों ने मुख्यमंत्री को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से मिल रहे लाभ के बारे में अवगत कराया। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि इस योजना से ही उनका नि:शुल्क उपचार संभव हो सका।

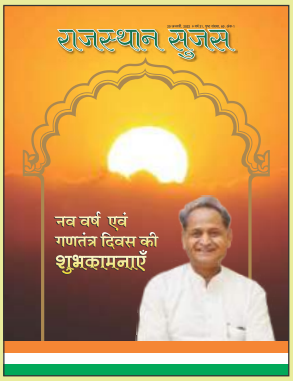

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

•

संपादक
अलका सक्सेना

•

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

•

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

•

कला
विनोद कुमार शर्मा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 94136-24352
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

नि:शुल्क वितरण

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 01 जनवरी, 2022

इस अंक में

सम्पादकीय	04
साकार हुआ सुशासन...	05
कल्याणकारी योजनाओं से...	10
युग गुरु विवेकानन्द...	13
जन सूचना पोर्टल...	16
कैशलेस आउटडोर उपचार...	20
खिलाड़ियों के लिये खोला खजाना...	22
हारेगा कोरोना, फिर जीतेगा राजस्थान	24
घर-घर औषधि...	28
पतंगबाजी को दिया उन्मुक्त गगन ...	32
आबू शरद महोत्सव...	39
गौरवमयी गाथा...	40
हर घर जल...	42
तालीम और स्वरोजगार से...	45
किसान कल्याण के 7 स्तम्भ...	46
बेजुबां जानवरों को राहत...	48
'सिर साटै, रूंख रहे, तो ई सस्तो'...	50
पहली महिला शिक्षक...	52
जल संरक्षण कार्य...	53
भौगोलिक पर्यटन की विरासत...	54
प्रदेशवासियों के नाम...	58

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी

09

15-18 वर्ष आयुवर्ग का वैक्सीनेशन

26

ज्यों तिल माही तेल है

36

वार्षिक कलैण्डर-2022

30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

राजस्थान ई-गवर्नेंस

14

मकर संक्रांति और उत्तरायण

34

श्री गंगानगर का किन्नू

56

नव आयामों का नव-विस्तार

नए साल का नया सवेरा हर जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली की रोशनी का प्रतीक बनकर आता है। बीते वर्ष की गतिविधियों, कमियों और इरादों तक अपनी पहुंच की समीक्षा के पश्चात् तरक्की की नई उम्मीदों के बीज बोने का एक और नया अवसर देता है नव-वर्ष। वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी चुनौतियों से जूझते विगत तीन वर्ष के सफलतम सुशासन को पूर्ण करने के पश्चात् मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार अब चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर सतत विकास की ओर उन्मुख है।

उत्तर को गतिमान भास्कर की ऊष्म-रश्मियों के साथ ही अब किशोरों-युवाओं में भी कोविड वैक्सीनेशन के सुरक्षा चक्र का आगाज किया जा चुका है। ''राजस्थान सतर्क है'' के मंत्र को ध्यान में रखकर कोरोना की पहली व दूसरी लहर का डटकर मुकाबला करते हुए हमने आप सबकी सकारात्मक साझेदारी से इन पर विजय पाई है। डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रोन अथवा तीसरी कोविड लहर के संभावित खतरों से बचाव के लिए भी आपकी महत्त्वपूर्ण भागीदारी एवं सभी सावधानियां अपरिहार्य है। मास्क, सेनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के दृढ़ संकल्प के साथ ही शत फीसदी टीकाकरण की दिशा में प्रदेश सरकार के अथक प्रयास निरन्तर जारी हैं।

नववर्ष के अरुणोदय में गांव-गांव तक विस्तार पा चुकी सुजस के सुधी पाठकगण का अथाह प्यार हमारे लिए किसी प्रेरणा पुंज से कम नहीं है। राजस्थान सरकार के मुखपत्र ''राजस्थान सुजस'' ने भी तीन दशकीय दीर्घ यात्रा पूरी कर चतुर्थ दशक का प्रारम्भ कर लिया है। बतौर प्रधान संपादक न सिर्फ मेरे लिए, अपितु सुजस टीम सहित आप सबके लिए यह गौरव की बात है।

नए साल पर युवाओं और आप सभी पाठकों को नई ऊर्जा के साथ समर्पित नववर्ष 2022 का यह प्रवेशांक आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे खुशी है। पाठकगण की समालोचनात्मक प्रतिक्रियाओं का सदैव की भांति स्वागत है। आप सबका स्नेह आपकी लोकप्रिय सुजस को यूं ही अनवरत मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ...

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

साकार हुआ सुशासन का मूलमंत्र

प्रदेशवासियों को मिली 13 हजार 195 करोड़ रुपये के 2512 विकास कार्यों की सौगात

प्रदेश में विगत तीन वर्ष में किए गए लोककल्याणकारी कार्यों से सेवा ही कर्म-सेवा ही धर्म का संकल्प साकार होता नजर आया है। राज्य सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, युवा, महिला सहित सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लिए न केवल एक से बढ़कर एक कल्याणकारी फैसले लिए, बल्कि उन्हें तत्परता के साथ लागू भी किया। इन फैसलों से राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से बढ़ा है और हर वर्ग को राहत मिली है। नित नए जनकल्याणकारी फैसले व उनका क्रियान्वयन यह उम्मीद जगाता है कि आने वाला समय विकास की दृष्टि से और बेहतरीन होगा।

पिछले तीन बजट की 87 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण

राज्य में पिछले तीन साल में सुशासन की नींव रखते हुए जनघोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप दिया गया और उसमें किए गए 70 प्रतिशत वादे दिसम्बर मध्य तक ही पूरे होते नजर आए। कोविड महामारी, राजस्व में बड़ी गिरावट, आर्थिक चुनौतियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद पिछले तीन बार के बजट की 87 प्रतिशत घोषणाओं की क्रियान्विति अभूतपूर्व उपलब्धि रही है। राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेशवासियों को करीब 13 हजार 195 करोड़ रुपये के 2512 विकास कार्यों की सौगात मिली है। प्रदेश में आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत 9 विभागों के करीब 9405 करोड़ रुपये लागत के 2408 कार्यों के शिलान्यास एवं करीब 3790 करोड़ रुपये लागत के 104 कार्यों के लोकार्पण के साथ की।

3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य

जब पहली और दूसरी लहर में कोविड का प्रसार जारी था, उस समय राज्य सरकार ने बेहतरीन प्रबंधन कर जीवन रक्षा का फर्ज निभाया। प्रदेशभर में हर वर्ग के सहयोग से 'कोई भूखा न सोए' का संकल्प साकार किया गया। लोगों के उपचार के लिए चार्टर प्लेन तक से दवा मंगवाई गई। अब ऐसा ही लोक हितैषी कदम उठाते हुए आमजन को इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंतामुक्त करने की दिशा में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारंभ की गई है। इसी तरह 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' से प्रदेश के लाखों

किसानों को बिजली बिल पर 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष तक का अनुदान मिल रहा है। इस योजना से करीब 3 लाख किसानों का विद्युत बिल शून्य (जीरो) हो गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंग्लिश मीडियम स्कूल

प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गई है। साथ ही, करीब 123 नए महाविद्यालय खोले गए, जिनमें 33 महिला कॉलेज शामिल हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12वीं कक्षा में 500 या इससे अधिक बालिकाएं होने पर कॉलेज खोलने का निर्णय भी महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान आवासन मंडल को पुनर्जीवित किए जाने में हर जन को आवास उपलब्ध करवाने की भावना नजर आती है।

राज्यों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना आवश्यक

राज्यों के विकास में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही, राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जल जीवन मिशन सहित अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्र सरकार से अपनी हिस्सा राशि बढ़ाए जाने को कहा है। राजस्थान जैसे विस्तार वाले एवं मरुस्थलीय भौगोलिक दशाओं वाले राज्य के लिए ये परियोजनाएं बहुत महत्त्व रखती हैं।

आज राजस्थान सीमित संसाधनों के बावजूद विकास के नए आयाम छू रहा है। लोकहित में चलाए गए प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। शहरों के विकास की परियोजनाओं को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग साकार करने में जुटा है।

इसी तरह किसान कल्याण की दिशा में सरकार ने कृषक कल्याण कोष का गठन, कृषि ऋण माफी, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति जैसे बड़े कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राजस्थान में सबसे अच्छा काम हुआ है। अब राज्य में कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की हैं। साथ ही, इन योजनाओं को निचले स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर गुड गवर्नेन्स के लक्ष्य को फलीभूत किया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा और पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। करीब एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और करीब एक लाख ही भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

कार्य तथा राशि अनुसार सूची सौगातें

	शिलान्यास A		लोकार्पण B		A+B	
विभाग	कार्य	राशि (करोड़ रु)	कार्य	राशि (करोड़ रु)	कार्य	राशि (करोड़ रु)
ऊर्जा	19	67.66	23	35.81	42	103.47
जल संसाधन	3	155.50	5	700.26	8	855.76
डेयरी	–	–	1	55.00	1	55.00
पीडब्ल्यूडी	6	1463.00	4	993.00	10	2456.00
वन	–	–	2	20.00	2	20.00
नगरीय विकास	6	339.60	2	59.71	8	399.31
स्वायत्त शासन	5	95.76	6	293.09	11	388.85
उद्योग	25	712.19	7	242.33	32	954.52
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2344	6571.11	54	1430.76	2398	8001.87
योग	2408	9404.82	104	3789.96	2512	13194.78

ये हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, लोकार्पण :– (59.71 करोड़)

- एलसी नं. 200 बस्सी, जयपुर में चार लेन आरओबी का निर्माण, 48.30 करोड़
- जयपुर में किशन बाग वानिकी परियोजना का लोकार्पण, 11.41 करोड़

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शिलान्यास :– (339.60 करोड़)

- जवाहर सर्किल जयपुर, यातायात सुधारीकरण, सौन्दर्यीकरण (44.19 करोड़)
- बी-2 बाईपास, जयपुर, यातायात सुधारीकरण, सौन्दर्यीकरण (155.06 करोड़)
- लक्ष्मी मन्दिर तिराहा, जयपुर, यातायात सुधारीकरण, सौन्दर्यीकरण (81.25 करोड़)
- लक्ष्मी मन्दिर तिराहा, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापना (3.40 करोड़)
- राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आन्तरिक साज-सज्जा (41.00 करोड़)
- पृथ्वीराज नगर दक्षिण में सीवरेज का कार्य (14.70 करोड़)

स्वायत्त शासन विभाग, लोकार्पण :– (293.09 करोड़)

- नगर परिषद किशनगढ़ में सीवरेज लाइन एवं एसटीपी अपग्रेडेशन 125.55 करोड़
- उदयपुर, बलीचा से गोवर्धन सागर तक स्मार्ट रोड का विकास 18.99 करोड़
- उदयपुर, पीपीपी, हाइब्रिड एनयूटी आधारित 3 एसटीपी की कमीशनिंग 80 करोड़
- न.नि. जयपुर हैरिटेज मुख्यालय भवन का मरम्मत एवं पुनरुद्धार 7.07 करोड़
- अनाजमण्डी चांदपोल, जयपुर में बहुमंजिला कार पार्किंग 14.84 करोड़
- जयपुर परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट रोड के तहत आईसीटी कार्य 46.64 करोड़

स्वायत्त शासन विभाग, शिलान्यास :– (95.76 करोड़)

- नगर परिषद सिरोही में टाउन हॉल का निर्माण कार्य 17.05 करोड़
- माखुपुरा, अजमेर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर ठोस कचरा परिशोधन संयंत्र एवं सेनेटरी लैंडफिल का निर्माण कार्य 15 करोड़
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जयपुर का विस्तार 44.61 करोड़
- कंवर नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण एवं खेल सुविधाएं और मौजूदा सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल का विस्तार कार्य 13.86 करोड़
- चारदीवारी क्षेत्र जयपुर में स्मार्ट हैरिटेज स्ट्रीट लाइट पोल्स का कार्य 5.24 करोड़

कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन विभाग, लोकार्पण :– (55 करोड़)

- मेट्रो डेयरी पाउडर प्लांट गोविन्दगढ़ जयपुर का लोकार्पण 55 करोड़

वन विभाग, लोकार्पण :– (20 करोड़)

- अभेड़ा पार्क, जिला कोटा
- सेन्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड क्लाइमेट चेंज, जयपुर

ऊर्जा विभाग, लोकार्पण :– (3581.69 लाख रुपए)

क्र.	कार्य का नाम	लागत (लाख रु)
जयपुर डिस्कॉम		
1.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, झिरी,धौलपुर	270.92
2.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, हाड़ों का पीपल्दा, बून्दी	202.44
3.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, बालाहेड़ा, दौसा	140.00
जोधपुर डिस्कॉम		
4.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, सरस्वती नगर, जोधपुर	137.00
5.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, डाबला, जोधपुर	157.00
6.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, रातानाड़ा, जोधपुर	82.15
7.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, दांताणी, सिरोही	190.00
8.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, काछौली, सिरोही	144.00
9.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, नौसर, बाड़मेर	171.00
10.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, हुड़ों की ढ़ाणी, बाड़मेर	82.16
11.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, देताणी, बाड़मेर	201.77
12.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, अरटा, बाड़मेर	126.75
13.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, हरियाली, बाड़मेर	190.88
14.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, स्वरूपदेसर, बीकानेर	140.00
15.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, कुचोर अगुनी, बीकानेर	140.00
16.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, शेरपुरा, बीकानेर	140.00
17.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, सियासर, बीकानेर	170.00
18.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, मकेरी, बीकानेर	260.00
19.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, बिदासरिया, बीकानेर	125.00
20.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, केऊ, बीकानेर	125.00
21.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, शेरूणा, बीकानेर	131.00
22.	33/11 के.वी. सब स्टेशन, मोमासर, बीकानेर	130.00
अजमेर डिस्कॉम		
23.	33/11 के.वी. जीएसएस, चान्दरवाड़ा	90.00

ऊर्जा विभाग, शिलान्यास:– (6765.90 लाख रुपए)

क्र.	कार्य का नाम	लागत (लाख रु)
जयपुर डिस्कॉम		
1.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, मछरिया, धौलपुर	187.23
2.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, राजपुर, धौलपुर	196.73
3.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, श्यामपुरा खुर्द, दौसा	169.97
4.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, चांदेरा, दौसा	116.23
5.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, बागावास अहिरान, जयपुर	124.80
6.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टे., महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डी.टी.ए. द्वि., जयपुर	220.00
जोधपुर डिस्कॉम		
7.	नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, सिवेरा, सिरोही	155.18
8.	सब ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, आलमसरिया, बाड़मेर	151.56

9. सब ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, छोटू, बाड़मेर	152.88
10. सब ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, बांखासर, बाड़मेर	171.63
11. नवीन 33/11 के.वी. सब स्टेशन, चावड़ा बस्ती में निर्माण, बीकानेर	140.00
12. सारसर, तह. सरदारशहर में 33 के.वी. सब स्टे. निर्माण, चूरू	246.77
13. ग्राम कानूता तहसील बीदासर में 33 के.वी. सब-स्टेशन, चूरू	130.75
अजमेर डिस्कॉम	
14. 33/11 के.वी. विद्युत ग्रिड, बरोड़िया, बांसवाड़ा	116.50
15. 33/11 के.वी. विद्युत ग्रिड, खेड़ाकेसुन्दा, प्रतापगढ़	305.30
16. 33/11 के.वी. विद्युत ग्रिड, निनोर, प्रतापगढ़	151.55
17. 33/11 के.वी. विद्युत ग्रिड, बड़वासकलां, प्रतापगढ़	140.70
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
18. 132 के. वी. जी.एस.एस. बोरखेड़ा (कोटा)	1968.17
19. 132 के. वी. जी.एस.एस. सुराणा (जालौर)	1919.95
योग	6765.90

जल संसाधन विभाग, लोकार्पण :– (700.26 करोड़)

- भांखडा कैनाल सिस्टम की सूरतगढ़ वितरिका, हनुमानगढ़ (32.87 करोड़)
- भीम सागर मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार, झालावाड़ (41.47 करोड़)
- माही कैनाल सिस्टम का नवीनीकरण कार्य, बांसवाड़ा (158.96 करोड़)
- बड़ा नया गांव लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य, बूंदी (63.56 करोड़)
- राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य, झालावाड़ (403.40 करोड़)

जल संसाधन विभाग, शिलान्यास :– (155.50 करोड़)

- कोटड़ी लघु सिंचाई परियोजना का कार्य, सीकर (39.84 करोड़)
- अनास नदी पर डागल एनिकट निर्माण कार्य, बांसवाड़ा (29.16 करोड़)
- सेई टनल की प्रवाह क्षमता बढ़ाने का कार्य, पाली (86.50 करोड़)

पीडब्ल्यूडी विभाग, लोकार्पण :– (993 करोड़)

- बनाड़-भोपालगढ़-कुचेरा (स्टेट हाईवे संख्या 63) 347 करोड़
- भावी-पीपाड.-खींवसर (स्टेट हाईवे संख्या 86सी) 145 करोड़
- जोधपुर-मारवाड़ जंक्शन-जोजावर (स्टेट हाईवे संख्या 61) 477 करोड़
- ओटीएस में नवनिर्मित एक्जीक्यूटिव हॉस्टल का शुभारंभ 24 करोड़

पीडब्ल्यूडी विभाग, शिलान्यास :– (1463 करोड़)

- मंगलाना-मकराना-बोरावड़, बिडियाड परबतसर ;एसएच 2बी) 174 करोड़
- हुरड़ा-बनेड़ा (स्टेट हाईवे संख्या 39ए) 127 करोड़
- मांगलियावास-पादूकलां सड़क का विकास (स्टेट हाईवे संख्या 102) 246 करोड़
- ब्यावर-पीसांगन-टेहला-कोड-अलनियावास सड़क विकास (एसएच 49-104) 250 करोड़
- किशनगढ़-अराई- मालपुरा (स्टेट हाईवे संख्या 7ई) 243 करोड़
- रामसीन-भीनमाल- रानीवाड़ा (स्टेट हाईवे संख्या 31) 423 करोड़

उद्योग विभाग, लोकार्पण :– (242.33 करोड़)

- औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा (25.49 करोड़)
- औद्योगिक क्षेत्र दुब्बी बिदारखा (30.34 करोड़)
- औद्योगिक क्षेत्र बांदापुर (चोपानकी विस्तार) (65.95 करोड़)
- औद्योगिक क्षेत्र एमटीसी अजमेर (5.07 करोड़)
- औद्योगिक क्षेत्र बड़ी सीड (101.97 करोड़)
- औद्योगिक क्षेत्र प्रतापगड़ विस्तार (9.14 करोड़)
- वन स्टॉप शॉप भवन का शुभारम्भ (4.37 करोड़)

उद्योग विभाग, शिलान्यास :– (712.19 करोड़)

- 25 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास (712.19 करोड़)

इन 25 औद्योगिक क्षेत्रों का हुआ शिलान्यास

क्र.	इकाई औद्योगिक क्षेत्र	लागत (लाख में)
1	भीलवाड़ा फतेहपुर समेलिया	4232.04
2	जोधपुर सोपड़ा	1459.43
3	सवाईमाधोपुर श्रीनगर	1285.24
4	बोरनाड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क	13473.56
5	बालोतरा रामनगर थोब	3138.47
6	जोधपुर लोहावट	2269.60
7	बांसवाड़ा बावलियापाड़ा	900.93
8	पाली बिठान	996.83
9	नागौर जायल	2037.82
10	सवाईमाधोपुर चोसला (टोंक)	1099.53
11	अजमेर मसूदा	921.68
12	आबूरोड पीपला रोहेड़ा	1160.98
13	पाली ढोला जांगीर	2670.19
14	जयपुर (ईपीआईपी) हुक्न (चाकसू)	3372.57
15	जयपुर (ईपीआईपी) निमोड़िया	4007.32
16	भरतपुर कोटरा	2456.72
17	कोटा तालाब गांव (बून्दी)	1577.23
18	अजमेर बड़ली	1941.26
19	जयपुर (आर) मथासुला	4378.70
20	सवाईमाधोपुर बोरखण्डी कलां	1059.76
21	बालोतरा चौहटन	2680.88
22	उदयपुर डांगी खेड़ा अमली	1418.28
23	राजसमंद कुरज	4591.07
24	अजमेर कालेसरा	2068.82
25	जयपुर (एस) तूंगा	6049.70

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोकार्पण :– (1430.76 करोड़)

- इन्द्रगढ़ वृहद् पेयजल योजना (चाकन बांध से) जिला बूंदी 73.93 करोड़
- चम्बल बूंदी वृहद् पेयजल योजना (क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन) 15.45 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डेगाना, नागौर एवं मेड़ता के 151 ग्राम 324.91 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डेगाना, मेड़ता के 176 ग्राम 176.65 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज- परबतसर के 110 ग्राम 221.92 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-मकराना के 119 ग्राम 240.02 करोड़
- नागौर लिफ्ट परियोजना के क्लस्टर पैकेज-डीडवाना एवं लाडनूं के 170 ग्राम 288.21करोड़
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 47 पेयजल ग्रामीण योजनाएं 89.67 करोड़

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिलान्यास :– (6571.11 करोड़)

- बीसलपुर-टोंक-देवली उनीयारा परियोजना, टोंक (200.29 करोड़)
- बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल योजना, जिला जयपुर (113.56 करोड़)
- बीसलपुर-दूदू-चाकसू पेयजल योजना, जिला जयपुर (108.62 करोड़)
- बीसलपुर-दूदू-फागी पेयजल योजना, जिला जयपुर (195.12 करोड़)
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाघेरी का नाका जिला राजसमन्द (133.48 करोड़)
- चूरू-बिसाउ (अलसीसर ब्लॉक) पेयजल परियोजना जिला चूरू (138.46 करोड़)
- बूंगी राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरू (173.02 करोड़)
- पाली के 10 ग्राम पंचायतों के 34 ग्रामों हेतु पेयजल परियोजना (146.85 करोड़)
- जवाई क्लस्टर-चतुर्थ, पाली के 224 ग्रामों हेतु पेयजल परियोजना (230.02 करोड़)
- तहसील जायल के 123 ग्रामों एवं 244 ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर (159.71 करोड़)
- तहसील लाडनूं के 102 ग्रामों एवं 261 ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर (205.97 करोड़)
- तहसील मेड़ता, रियां एवं भेरूंदा के 181 ग्रामों एवं 142 ढाणियों हेतु पेयजल परियोजना, जिला नागौर (190.82 करोड़)
- जयसिंहपुरा खोर शहरी पेयजल वितरण व्यवस्था के संवर्धन कार्य (30.75 करोड़)
- राजगढ़ (चूरू) शहरी पेयजल योजना के संवर्धन कार्य (46.85 करोड़)
- नागौर लिफ्ट परियोजना डेगाना, नागौर, मेड़ता, खींवसर फेज-1 पैकेज-3 (183.74 करोड़)
- नावां तहसील के 97 ग्रामों व ढाणियों हर घर जल की परियोजना (188.17 करोड़)
- 2326 ग्रामीण पेयजल योजनाएं (4125.68 करोड़)

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में तीन वर्ष का सफल सुशासन पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की शृंखला में जवाहर कला केंद्र में ''सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म'' संकल्प की थीम पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी ''आपका विश्वास, हमारा प्रयास'' का आयोजन किया गया। शुभारम्भ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर पहुंचकर विभिन्न प्रकाशनों पर फीडबैक दिया एवं राजस्थान सरकार के मुखपत्र ''राजस्थान-सुजस'' सहित विभिन्न प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया। उन्होंने विभागों द्वारा प्रदर्शनी में लगाई गई सभी स्टॉल्स की विजिट कर वहां उपस्थित विभाग अधिकारियों एवं आमजन से भी बात की।

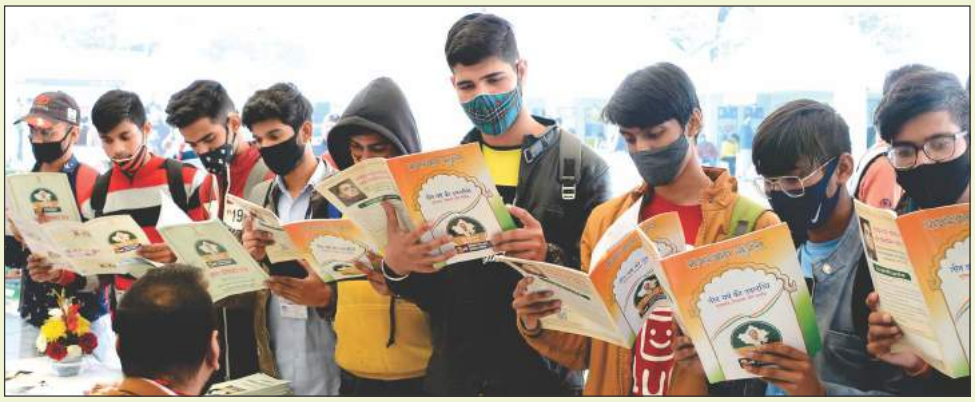

कल्याणकारी योजनाओं से जनजीवन सुगम

प्रदेशवासियों को मिली 1122 करोड़ के 1194 विकास कार्यों की सौगातें

राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले तीन वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं वंचित, पिछड़े एवं जरूरतमंद वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और आमजन के जीवन को सुगम बनाने का काम कर रही हैं। हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर व्यक्ति को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा और हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास इन योजनाओं में नजर आता है।

राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर भी विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के साथ ही 'जागृति बैक टू वर्क योजना', 'आईएम शक्ति उड़ान योजना', 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' और 'डीबीटी वाउचर योजना' जैसी नवाचार युक्त योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में 12 विभागों के करीब 1122 करोड़ रुपए के 1194 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। इसमें करीब 454 करोड़ रुपए की लागत के 90 विकास कार्यों का शिलान्यास और 668 करोड़ रुपए की लागत के 1104 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। 'जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप' एवं 'ई-मित्र एट होम' का शुभारंभ तथा उड़ान योजना के शुभंकर, संचार रणनीति पुस्तिका एवं पोस्टर का जारी किए गए हैं। इसके अलावा 8 एम्बुलेंस और 2 बाइक एम्बुलेंस भी जनसेवा को समर्पित हुए हैं। प्रदेशभर में ऐसी करीब 100 एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में जानी हैं।

किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन वितरण के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के पहले चरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राज्य सरकार की महिलाओं एवं किशोरियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है। अब राज्य सरकार इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ

आईएम शक्ति उड़ान योजना | **जागृति बैक टू वर्क योजना** | **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना** | **डीबीटी वाउचर योजना**

तथा अधिक से अधिक जनभागीदारी का प्रयास कर रही है। ताकि गांव-ढाणी तक महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार की अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति के भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पहले दुष्कर्म के करीब 33 प्रतिशत केस कोर्ट के इस्तगासे से दर्ज होते थे। अब वे कम होकर 15 प्रतिशत पर आ गए हैं। इसी प्रकार महिला अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का पद सृजित होने से दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान का औसत समय 274 दिन से घटकर 73 दिन रह गया है। थानों में फरियादियों की सुनवाई के लिए स्वागत कक्ष निर्माण की अनूठी पहल की गई है। इसका मकसद थाने में आने वाले हर फरियादी की बात मान-सम्मान के साथ सुनना है। प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं।

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 26 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। इसे यह शून्य स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का क्रांतिकारी फैसला लिया है। इन विद्यालयों में करीब 88 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। लोगों में इन विद्यालयों के प्रति विशेष उत्साह देखते हुए राज्य सरकार ने 5 हजार की आबादी वाले गांव-कस्बों में भी करीब 1200 स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस दिशा में दिसम्बर में 178 और स्कूल प्रारंभ किए गए हैं।

साथ ही, 25 प्री-प्राइमरी ब्लॉक एवं छात्रावास का भी लोकार्पण किया गया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले लेकर गांव-ढाणी तक लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना के बाद निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसे बड़े कदम हैं, जिनसे गरीब परिवार इलाज के खर्च से चिंतामुक्त हो गए हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में करीब 28 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा तथा दूसरे चरण में प्रदेश की करीब 1.20 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेगा। इसी प्रकार जागृति बैक टू वर्क योजना से महिला सशक्तीकरण की भावना को मजबूती मिलेगी।

लोकार्पण एवं शिलान्यास

गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लोकार्पण :– (106.24 करोड़)

- 543 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष
- 12 नवीन पुलिस थाना भवन

पुलिस थाना दानपुर (बांसवाड़ा), पुलिस थाना सल्लोपाट (बांसवाड़ा), पुलिस थाना हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), पुलिस थाना सोजतसिटी (पाली), पुलिस थाना साण्डेराव (पाली), पुलिस थाना जैतारण (पाली), पुलिस थाना तूंगा (आयुक्तालय जयपुर), पुलिस थाना एसओजी (जयपुर), पुलिस थाना साइबर क्राइम (जयपुर), पुलिस थाना मेहन्दवास (टोंक), पुलिस थाना राजगढ़ (अलवर), महिला पुलिस थाना दौसा (दौसा)

- 01 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवन
- 14वीं बटालियन आरएसी पहाड़ी (भरतपुर) का भवन
- महाराणा प्रताप बटालियन हथूनिया (प्रतापगढ़) का भवन
- पुलिस लाइन ग्रामीण, जयपुर में आवासीय भवन
- जोधपुर एफएसएल में डीएनए प्रयोगशाला
- स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर
- ग्राउंड ट्रूथिंग ऐप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लोकार्पण :– (7.00 करोड़)

अम्बेडकर पीठ मूण्डला में 2 छात्रावास (7.00 करोड़)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शिलान्यास :– (96.15 करोड़)

- देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, मसूदा, अजमेर (27.64 करोड़)
- देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा (27.63 करोड़)
- देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, रास, जिला पाली (27.63 करोड़)
- देवनारायण बालिका छात्रावास, जामडोली, जयपुर (4.85 करोड़)
- देवनारायण बालिका छात्रावास, नदबई, भरतपुर (2.80 करोड़)
- रा. अम्बेडकर अनु. जनजाति बालक छात्रावास, सज्जनगढ,बांसवाड़ा (2.80 करोड़)
- रा. अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, प्रतापनगर, जयपुर (2.80 करोड़)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के लोकार्पण :– (2.74 करोड़)

- कौशल विकास केन्द्र, खानपुरा, जिला–दौसा (2.74 करोड़)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के शिलान्यास :– (14.66 करोड़)

- रजोल मुख्य मार्ग से बामनवाड़ा तक सड़क डामरीकरण, ग्राम पंचायत रजोल जिला–उदयपुर (83 लाख)
- बी.टी. सड़क निर्माण ए/आर अडूवापाडा से अम्बाको तक, ग्राम नादीया, बांसवाड़ा (1.28 करोड़)
- धरियावद पारसोला मुख्य रोड से जगलावदा मुंगाणा रोड तक वाया नायक टाण्डा डामरीकरण मय इन्टरलॉकिंग सड़क, धरियावद, जिला–प्रतापगढ़ (91 लाख)
- बिणझारी माता से हाईवे रूपवास तक 1.9 किमी डामरीकरण, बांदीकुई जिला–दौसा (50 लाख)
- नहर निर्माण कार्य बायी मुख्य नहर लाइनिंग कार्य आरडी 0 से 6450 मी. भंवर सेमला सिंचाई परियोजना, पीपलखूंट, जिला–प्रतापगढ़ (3.23 करोड़)
- 18 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य (1.80 करोड़)
- 25 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य (1.92 करोड़)
- 12 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य (93 लाख)
- 6 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य (54 लाख)
- बेणेश्वर धाम एनिकट मरम्मत कार्य जिला–डूंगरपुर (2.72 करोड़)

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लोकार्पण :– (18.29 करोड़)

- महिला आईटीआई, टोंक (4.99 करोड़)
- सद्भावना मण्डप भवन, बम्बोरा (3.09 करोड़)
- राजकीय बालिका छात्रावास, बम्बोरा (1.91 करोड़)
- राजकीय बालक छात्रावास, बासनी बेलिमा (2.40 करोड़)
- राजकीय बालिका छात्रावास, नागौर (2.40 करोड़)
- कॉमन सर्विस सेन्टर, झुन्झुनूं (1.40 करोड़)
- राजकीय माध्यमिक विद्यालय कन्धारवाड़ी (87 लाख)
- रा.बा.उ.मा.वि अम्बामाता, उदयपुर (65 लाख)
- रा.बा.उ.मा.वि आयड़ धूलकोट (43 लाख)
- स्व. पं. खेमराज रा.उ.प्रा.वि. ताम्बावती मार्ग (15 लाख)

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शिलान्यास :– (17.92 करोड़)

- कॉमन सर्विस सेन्टर, जैसलमेर (1.40 करोड़)
- यूनानी मेडिकल कॉलेज में बालक छात्रावास, टोंक (3.38 करोड़)
- राजकीय बालिका छात्रावास भवन निर्माण, लाडनूं, नागौर (2.40 करोड़)
- कॉमन सर्विस सेन्टर, बांसवाड़ा (1.40 करोड़)
- कॉमन सर्विस सेन्टर, उदयपुर (1.40 करोड़)
- अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, जयपुर (7.94 करोड़)

स्कूल शिक्षा विभाग के लोकार्पण :– (41.22 करोड़)

- 25 प्री–प्राइमरी ब्लॉक एवं छात्रावास (35.20 करोड़)
- 178 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शुभारम्भ 94 आईसीटी लैब्स का लोकार्पण (6.02 करोड़)

तकनीकी शिक्षा विभाग के लोकार्पण :– (10.40 करोड़)

- अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर में लेबोरेटरी ब्लॉक–1 (2.78 करोड़)
- अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर में एससी/एसटी छात्र छात्रावास (2.56 करोड़)
- अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर में 100 केवी सोलर पैनल की स्थापना
- अभि. महा वि., भरतपुर में वेयर हाउस एवं पम्प हाउस ऑपरेटर कक्ष (30 लाख)
- एमएलवी टैक्सटाइल एण्ड इंजी. कॉलेज, भीलवाड़ा में सेमिनार हॉल (1.34 करोड़)
- अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी (47 लाख)

तकनीकी शिक्षा विभाग के शिलान्यास :– (2.95 करोड़)

- अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर में एससी/एसटी छात्रावास (2.95 करोड़)

उच्च शिक्षा विभाग के लोकार्पण :– (34.50 करोड़)

- राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (6 करोड़)
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू (6 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़ (6 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (6 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में प्रयोगशाला (1.60 करोड़)
- एमबीसी रा. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर में निर्माण कार्य (1.40 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय, उनियारा (टोंक) में निर्माण कार्य (1 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय सांभरलेक (जयपुर) में भवन निर्माण (1 करोड़)
- श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में निर्माण कार्य (1 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) में निर्माण कार्य (1 करोड़)
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य (3.50 करोड़)

उच्च शिक्षा विभाग के शिलान्यास :– (10.70 करोड़)

- राजकीय महाविद्यालय बस्सी, जिला जयपुर का भवन निर्माण (5.35 करोड़)
- राजकीय महाविद्यालय विराटनगर, जिला जयपुर का भवन निर्माण (5.35 करोड़)

कौशल एवं उद्यमिता विभाग के 20 आईटीआई का लोकार्पण:– (146.31 करोड़)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लोकार्पण :– (1.5 करोड़)

- भरतपुर में इन्क्यूबेशन सेन्टर (1.5 करोड़)

चिकित्सा विभाग के कार्यों का लोकार्पण :– (286.03 करोड़)

- 37 अस्पतालों में 12 बिस्तर के आईसीयू, कुल 424 बेड (24.89 करोड़)
- ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट– 93 (86.34 करोड़)
- पीकू, नीकू, मॉड्यूर ऑपरेशन थिएटर – 28 (94.45 करोड़)
- सीएचसी एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र – 33 (80.35 करोड़)

चिकित्सा विभाग के शिलान्यास :– (311.46 करोड़)

- पीएचसी, सीएचसी–53 (114.82 करोड़)
- पीकू, नीकू–10 (84.76 करोड़)
- भीलवाड़ा में अस्पताल एवं छात्रावास (111.88 करोड़)

महिला एवं बाल विकास विभाग के लोकार्पण :– (2 करोड़)

सखी वन स्टॉप सेन्टर नवीन भवन (जिला–झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, चूरू एवं बूंदी)

सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक युग गुरु

स्वामी विवेकानन्द

आशाराम खटीक
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

स्वामी जी ने क्यों कहा था कि भारत के युवाओं को गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। दुनिया में सनातन धर्म और भारत की प्रतिष्ठा की बात आए और स्वामी विवेकानंद का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणापुंज हैं।

''युवा'' अर्थात एक ऐसा ऊर्जावान शब्द जो सक्रियता, सकारात्मकता और स्फूर्ति का द्योतक होने के साथ ही कर्मशील, शक्तिमान व गतिवान होने का परिचायक भी है। प्रतिवर्ष बारह जनवरी को स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 'अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस' एवं 'कैरियर गाइडेंस डे' मनाया जाता है। स्वामी विवेकानन्द भारत के ऐसे मानवतावादी वैचारिक मार्गदर्शक एवं आध्यात्मिक चिन्तक थे जिनके विषय में गुरुदेव रवीन्दनाथ टैगोर ने रोम्यां रोलां को लिखा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले विवेकानन्द का अध्ययन कीजिए। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं।

स्वामी जी ने एक बार कहा था-हमारा सबसे बड़ा दोष परमत असहिष्णुता है। इसलिए सहिष्णुता, शान्ति और सहयोग ही हमें एक-दूसरे के निकट ला सकता है। उनका कहना था कि ''धर्म ग्रहणशील होना चाहिए और ईश्वर संबंधी अपने विश्वासों में भिन्नता के कारण एक-दूसरे का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत मानव-संबंधी सिद्धांत के तहत आने चाहिए और जब धर्म इतने उदार हो जाएंगे तो उनकी कल्याणकारी शक्ति सौ गुना हो जाएगी। धर्मों में अद्भुत शक्ति है लेकिन उनकी संकीर्णता के कारण उनसे लाभ की जगह हानि ज्यादा हुई है।''

बतौर शिकागो वक्तृता स्वामीजी ने जब सितम्बर, 1893 में अमेरिका के वैश्विक धर्म सम्मेलन को ''अमेरिका निवासी भगिनी तथा भ्रातृगण'' अर्थात् अमेरिकावासी बहन और भाई कहकर संबोधित किया, तो हर्ष और उत्साह की ऐसी करतल महाध्वनि गूंज उठी कि वह कई मिनट तक होती रही। कारण यह था कि प्राच्य के इस सन्यासी ने स्त्रियों को पहले स्थान दिया और सारे विश्व को अपना कुटुम्ब कहकर संबोधित किया। सौहार्द और स्नेह के साथ आर्यावृत्त भारत का धार्मिक प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि ''मुझे ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' तथा 'सब धर्मों को मान्यता प्रदान' करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन् समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूं जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द Exclusion का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं! .... मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलम्बियों को आश्रय दिया है।'' अपने व्याख्यान का उपसंहार करते हुए भी स्वामीजी ने आशा व्यक्त की कि साम्प्रदायिकता, कट्टरता, एवं धर्मान्धता का शीघ्र ही विनाश होगा।

चरैवेति-चरैवेति के इस युग में मानवमन विश्वमन से संयुक्त हो गया है। आज देश की आधी से अधिक आबादी युवा है, इसीलिए भारत युवाओं का देश कहा जाता है, और यही युवा ऊर्जा देश एवं प्रदेश के विकास की द्योतक है।

राजीव–2021 डिजिटल क्विजथॉन पुरस्कार वितरण समारोह

राजस्थान ई–गवर्नेंस में अग्रणी

विजयी विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

आज शासन, प्रशासन और जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तकनीक का महत्व बढ़ गया है। इसे देखते हुए राजस्थान में भी सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर ई–गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिली है। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसी योजनाएं प्रदेश के युवाओं के लिए अपूर्व अवसर प्रदान कर रही हैं और उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की जयंती पर कॉलेज शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित ''राजीव–2021 डिजिटल क्विजथॉन'' प्रतियोगिता में विजयी रहने पर जयपुर जिले के 20 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 9 विजेताओं को टैब और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 11 विजेताओं को मोबाइल फोन दिया गया। क्विजथॉन में 29 जिलों के 165 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें पुरस्कार स्वरूप 75 प्रतिभागियों को एक–एक टैब तथा 90 प्रतिभागियों को एक–एक मोबाइल फोन दिया गया है। इन विजेताओं को यह पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने इन विजेताओं से संवाद के दौरान कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक रहे हैं। उन्होंने ई–गवर्नेंस और आईटी का लाभ घर–घर पहुंचाने का जो सपना देखा था, आज वह साकार हो रहा है। यह शुभ संकेत है कि युवा जागरूकता के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर और आईटी का उपयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि नई पीढ़ी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, स्व. इंदिरा गांधी, स्व. राजीव गांधी जैसे महान नेताओं की देश के विकास के प्रति सोच और सिद्धांतों को अपनाकर आगे बढ़े। शिक्षा के साथ–साथ युवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी काम करें। इससे उन्हें नये अनुभव मिलेंगे और उनके व्यक्तित्व का विकास होगा। विद्यार्थियों का मानना है कि अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल की योजना से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे उच्चस्तरीय

प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना से युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संबल मिला है। साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और उड़ान जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

क्विजथॉन ने युवाओं में उत्साह का संचार किया है। इनमें 17 से 23 आयु वर्ग के 59 हजार 568 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया और 29 जिलों के 165 विद्यार्थी विजेता रहे। छात्राओं ने क्विजथॉन में छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तीनों प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पर छात्राएं रही हैं।

''राजीव-2021 डिजिटल क्विजथॉन'' प्रतियोगिता में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति एवं कम्प्यूटर, स्थानीय शासन में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से सुशासन तथा सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता विषयक तीन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं। विजेताओं में56 छात्राएं हैं।

बच्चों से मिलकर उनकी पढ़ाई के बारे में ली जानकारी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाड़ा पदमपुरा के बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में बात की।

पदमपुरा से लौटते समय एक कोचिंग सेंटर के बाहर कतार में बैठकर मॉडल पेपर हल कर रहे बच्चों को देख मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवाया और उनसे आत्मीयता से बातचीत की। श्री गहलोत ने इन बच्चों से उनकी कक्षा, पाठ्यक्रम, पढ़ाई आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वहां मौजूद अभिभावकों ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाने के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ जाते हैं। पहली बार राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है। सरकार की यह पहल निश्चय ही सराहनीय है। इसका फायदा ग्रामीण बच्चों को होगा।

सूचना के अधिकार के संकल्प को साकार कर रहा राजस्थान का 'जन सूचना पोर्टल'

हर दिन औसतन 1.21 लाख लोग विजिट कर रहे हैं जन सूचना पोर्टल, हर दिन एक्सेस हो रहीं 1 लाख से अधिक सूचनाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की भावना और जन अधिकार कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप काम करते हुए संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की पालना में स्थापित 'जन सूचना पोर्टल' इसी संकल्प को साकार कर रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक 115 विभागों की 260 योजनाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं और आमजन इस पर 562 तरह की जानकारियां हासिल कर रहे हैं।

सफलता के आंकड़े

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सूचना के अधिकार के प्रारंभ से ही समर्थक रहे हैं। उनकी मंशा है कि आम आदमी को सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री की

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक

पहल पर राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल की परिकल्पना की और इसे साकार करते हुए 13 सितंबर, 2019 को पोर्टल प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया। विजिटर्स के आंकड़े इस पोर्टल की सफलता की पुष्टि करते हैं। लगभग 28 माह के समय में इस पोर्टल को 10.23 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया है और इस पर 9.73 करोड़ से अधिक सूचनाएं अभी तक एक्सेस की जा चुकी हैं। यदि इस आंकड़े की प्रतिदिन के हिसाब से गणना की जाए तो इस पोर्टल को औसतन 1.21 लाख से अधिक लोगों ने हर दिन विजिट किया है और हर दिन एक लाख से अधिक सूचनाएं इस पोर्टल पर एक्सेस की जा रही हैं।

क्या है जन सूचना पोर्टल

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

राजस्थान देश में पहला राज्य है, जिसने 'आपकी सूचना, आपका हक' की परिभाषा को अपनाते हुए सूचना को 'जन सूचना पोर्टल' के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं आमजन तक पहुंचा दी हैं। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आमजन को सूचनाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (2) की मूल भावना से प्रेरित है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं सरल भाषा में एक ही प्लेटफार्म पर मिल रही हैं। इससे जहां आम आदमी को राहत मिल रही है, वहीं सरकारी कामकाज में गति आ रही है, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार से निजात मिल रही है, सरकारी विभागों से आरटीआई के तहत मांगी

जाने वाली जानकारियों की अर्जियों में कमी आ रही है और आम आदमी को संबंधित जानकारी घर बैठे सुलभ हो पा रही है।

वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौर में तो इस पोर्टल की प्रासंगिकता और भी बढ़ी है। आमजन घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को आसानी से देख सकते हैं।

राजस्थान में सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार को लेकर राजस्थान में ही जन आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की अगुवाई में वर्ष 1994 में पाली जिले के कोटकिरान से हुई थी। वर्ष 2005 में श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सूचना के अधिकार अधिनियम की परिकल्पना की, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने लागू किया। यह अधिनियम सरकार के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। राजस्थान में यह अधिनियम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल के समय लागू कर दिया गया और जितना कार्य इस क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने किया, उसकी देश के अन्य राज्य में कोई मिसाल नहीं।

राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हो रहा काम

राजस्थान के 'जन सूचना पोर्टल' की तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सूचना पोर्टल पर काम हो रहा है। इन राज्यों के अधिकारियों ने इसके लिए राजस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया है। प्रदेश में जवाबदेह प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011, सुनवाई का अधिकार, 2012 अधिनियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,

2012 जैसे कानून भी लागू किए थे।

इंटीग्रेशन का काम लगातार जारी

पोर्टल पर सूचनाओं के इंटीग्रेशन का काम लगातार जारी है। आमजन की सुविधा के लिए नए मोड्यूल भी पोर्टल में जोड़े जा रहे हैं। इससे यह पता लग सकेगा कि योजना के संभावित लाभार्थियों की कुल संख्या में से कितनों को लाभ दिया जा चुका है, साथ ही व्यक्ति स्वयं से संबंधित सामान्य जानकारियां पोर्टल पर अपलोड कर यह जान सकेगा कि वह राज्य सरकार की किन योजनाओं के लिए पात्र है तथा पोर्टल पर ही उनके लिए आवेदन भी कर सकेगा।

कहा जा सकता है कि संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन के लिए हर आमजन को सभी सूचनाएं उनके हाथों में पहुंचाने के मामले में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है, जिसका अनुसरण देश के अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं।

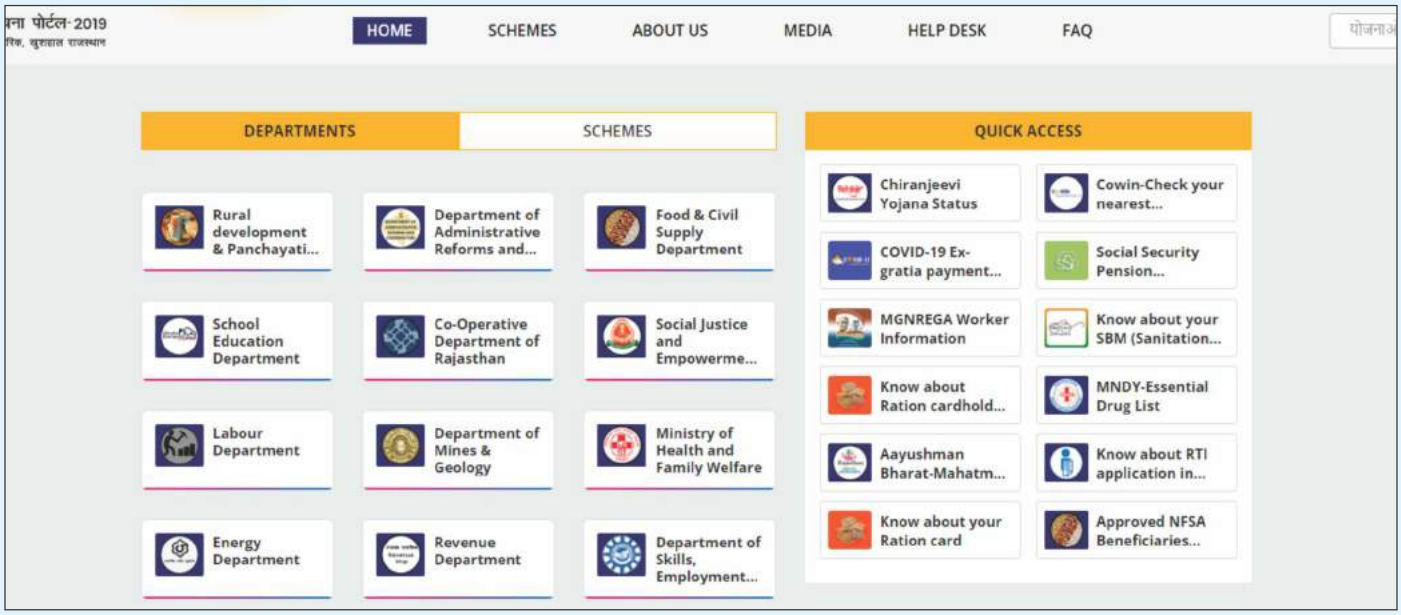

जन कल्याण ही प्राथमिकता ही प्रतिबद्धता

संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन को समर्पित
जन कल्याण पोर्टल

राजस्थान सरकार जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जनता का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनकल्याण पोर्टल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की इस मंशा को पूरा करता है, 'जन कल्याण ही प्राथमिकता जनकल्याण ही प्रतिबद्धता।' इसी संकल्प के साथ लॉन्च किए गए पब्लिक वेलफेयर पोर्टल में राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

क्या है जन कल्याण पोर्टल?

<https://jankalyan.rajasthan.gov.in/>

जन कल्याण पोर्टल राजस्थान सरकार के सभी विभागों और जिलों की सार्वजनिक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। सरकारी सूचनाओं की पहुंच आमजन को आसानी से एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। यहां सूचना बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से उपलब्ध है और विभिन्न रूपों में आवश्यकताओं के अनुसार खोजी जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार का इस संयुक्त प्रयास को 'पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन' को साकार करने के लिए विकसित किया गया है।

यह पोर्टल एक अभिनव ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसमें एक ही स्थान पर निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं:

- जनहित में जारी सरकारी दस्तावेज।
- राज्य सरकार की सभी योजनाएं और सेवाएं, जो राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संचालित की जा रही हैं।
- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की जानकारी।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा होस्ट की जाने वाली वेबसाइट और मोबाइल ऐप।
- 'सुशासन' के संकल्प को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, जिनमें मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं, बजट घोषणाएं, कैबिनेट निर्णय, जन घोषणा पत्र, नई पहल, रोजगार, उद्घाटन और कोविड -19 प्रबंधन शामिल हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के लिए राज्य सरकार को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां।
- राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की परियोजनाओं अथवा कार्यों की जानकारी।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधनों सहित राज्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के वीडियो।
- वीडियो/ऑडियो सहित विभिन्न जागरुकता सामग्री, जो जनता को सूचना के लिए जारी की जाती है।

18 दिसंबर, 2020 को लॉन्च हुआ यह पोर्टल राज्य भर में सभी विभागों और जिलों को कवर कर रहा है और नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से अपने नाम को साकार कर रहा यह पोर्टल प्रदेश के आमजन को एक ही स्थान पर सभी सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा है।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सेवा ही कर्म
सेवा ही धर्म
3 वर्ष आपका विश्वास हमारा प्रयास

"राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख–समृद्धि, स्वस्थ जीवन और चहुंमुखी विकास की कामना करता हूँ। आइए हम सब मिलकर राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी निष्ठा एवं संकल्पबद्धता से अपने कदम बढ़ाएं और मन, वचन व कर्म से इसमें सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाएं।"

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

खुशहाल जनता, समृद्ध राजस्थान, 3 वर्षों में हर चेहरे पर मुस्कान

तीन वर्ष की उपलब्धि: सुशासन, विकास और समृद्धि

• बेहतरीन कोरोना प्रबंधन
राजस्थान मॉडल स्टेट। दुनियाभर में सराहना। निकटवर्ती राज्यों के लोगों का भी किया मुफ्त इलाज

• कोरोना में 'कोई भूखा ना सोए' का संकल्प
32 लाख निराश्रित परिवारों को दी गई, प्रति परिवार 5500 रुपए की सहायता

• मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
प्रत्येक परिवार को मिल रहा है 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज

• जन घोषणा पत्र को किया नीतिगत दस्तावेज घोषित
70 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे

• अब तक 21 लाख किसानों का लगभग 15000 करोड़ रुपए का ऋण माफ

• 5 वर्ष तक किसानों के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं

• मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
प्रतिमाह 1000 रुपए बिजली बिल अनुदान। छोटे किसानों का बिजली बिल हुआ लगभग शून्य, अब तक 18000 करोड़ रुपए का अनुदान जारी

• एक लाख बेरोजगारों को मिली सरकारी नौकरी, एक लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन, शीघ्र ही होगी नियुक्ति

• राज्य के 33 जिलों में से 30 में खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज

• इंदिरा महिला शक्ति योजना
महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की निधि

उड़ान योजना
• समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण

• महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल
अब तक 87293 विद्यार्थी नामांकित, 5000 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव और कस्बे में खोले जा रहे 1200 विद्यालय

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विभिन्न कार्यों व योजनाओं का
शुभारम्भ • शिलान्यास • लोकार्पण

शनिवार, 18 दिसम्बर, 2021

ऊर्जा, जल संसाधन, पी डब्ल्यू डी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, वन, डेयरी, कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं-कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास

कुल कार्य – 2512 कुल राशि – 13186 करोड़

शुभारम्भ

उड़ान

रविवार, 19 दिसम्बर, 2021

समस्त किशोरियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना

एवं

गृह, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक, टीएडी, स्कूल/उच्च/तकनीकी शिक्षा एवं कौशल एवं रोजगार, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आयोजना विभाग की विभिन्न योजनाओं-कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास

कुल कार्य – 1207 कुल राशि – 1306 करोड़

अधिक जानकारी के लिए जनकल्याण पोर्टल **www.jankalyan.rajasthan.gov.in** देखें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में 67 लाख लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा

आउटडोर उपचार की ऑनलाइन एवं पेपरलेस सुविधा प्रदान करने वाला

देश का पहला राज्य बना राजस्थान

राज्यकर्मियों एवं राजकीय पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजनों को अब चिकित्सा के समय किसी भी प्रकार की नकद राशि जमा नहीं करानी पड़ रही है सभी प्रकार की बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत् राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों (लगभग 900) में लगभग 67.5 लाख लोगों को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस उपचार सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट (वर्ष 2021-22) में घोषणा की थी कि सीजीएचएस की तरह ही राज्य में भी कैशलेस एवं बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरजीएचएस योजना लागू की जायेगी।

ई-गवर्नेन्स की संकल्पना को व्यावहारिक रूप देते हुए आरजीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस इनडोर, डे-केयर एवं आउडोर उपचार की आरजीएचएस वेब पोर्टल (www.rghs.rajasthan.gov.in) द्वारा ऑनलाइन एवं पेपरलेस सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है।

आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी

योजना के अन्तर्गत विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राज्य सरकार के सरकारी, अर्द्धसरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को शामिल किया गया है।

अरुण जोशी
अतिरिक्त निदेशक

आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया

- लाभार्थी के लिए जनाधार पंजीयन संख्या/जनाधार संख्या होना आवश्यक है।
- आरजीएचएस में पंजीयन लाभार्थी की एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा।
- सेवारत कार्मिक अपनी एसएसओ आईडी (जी2जी) के द्वारा लॉग-इन कर पंजीयन पूर्ण कर सकते हैं।
- राज्य के पेंशनर्स एवं स्वायत्तशासी संस्थानों के सेवानिवृत एवं सेवारत कार्मिकों को एसएसओ आईडी (जी2सी) विकल्प से आरजीएचएस पंजीयन करना होगा।
- पंजीयन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम एसएसओ आईडी से लॉग-इन कर आरजीएचएस आइकन पर क्लिक करें, जनाधार पंजीयन संख्या/जनाधार संख्या भरें एवं प्रदर्शित फैमिली डिटेल्स में से आरजीएचएस परिवार को अपनी श्रेणी अनुसार चुनें। अपना और/अथवा परिवार सदस्य की एम्प्लॉय आईडी/पीपीओ नम्बर आदि को भरें। Validate करने के

पश्चात् पंजीकरण प्रक्रिया को सबमिट कर सफलतापूर्वक पंजीकरण का मैसेज प्राप्त करें।

- पंजीकरण सफलतापूर्वक होने पर अपना आरजीएचएस कार्ड देख सकते हैं।

आरजीएचएस कार्ड

ऑनलाईन पंजीकरण के पश्चात् आरजीएचएस लाभार्थी एवं सभी आश्रित परिजनों के सम्पूर्ण विवरण के साथ आरजीएचएस कार्ड प्रिंट करें। आरजीएचएस कार्ड से पूरे परिवार को एक आजीएचएस कार्ड नम्बर प्राप्त होगा।

समस्या समाधान

- योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी एवं समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन नम्बर 181 पर फोन कर सकते हैं। तथा ई-मेल के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in
- helpd.serving.rghs@rajasthan.gov.in
- helpd.pensioner.rghs@rajasthan.gov.in

आरजीएचएस में चिकित्सा प्रक्रिया-ऑनलाइन पंजीकरण

- ऑनलाईन पोर्टल (www.rghs.rajasthan.gov.in) पर पारदर्शी संचालन किया जाता है।
- इसके अन्तर्गत आरजीएचएस श्रेणियों के आधार पर लाभार्थियों का पोर्टल पर पंजीकरण होता है।
- आरजीएचएस कार्ड संख्या द्वारा लाभार्थी की पहचान होती है।
- निर्धारित समय-सीमा में पूर्णत: ऑनलाइन दावा निस्तारण।

बेहतर व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं

- 01 जुलाई 2021 से पात्र लाभार्थियों को इनडोर एवं डे-केयर का कैशलेस लाभ एवं 01 नवम्बर 2021 से ऑनलाइन ओपीडी एवं कैशलेस दवाईयों के लाभ का शुभारम्भ।
- आईपीडी एवं डे-केयर ईलाज हेतु समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस ईलाज, दवाईयों हेतु कॉनफेड एवं उपभोक्ता भण्डार आरजीएचएस अनुमोदित निजी फॉर्मा स्टोर से लेने की सुविधा।
- पात्र परिवारों को राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से सीजीएचएस वर्णित 1856 पैकेज दरों पर उपलब्धता।
- परिवार कल्याण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार नोडल विभाग एवं (बीमा), प्रशासनिक विभाग हैं। योजना के संचालन के लिए पृथक आरजीएचएस कार्यालय का गठन किया गया है।

बारां जिले के छबड़ा की श्रीमती पार्वती पारीक के लिये आरजीएचएस वरदान साबित हुआ है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जयपुर में गत 1 वर्ष से उपचार करवा रही पार्वती के इलाज पर प्रतिमाह लगभग 1 लाख रूपये का खर्च आता है जिसकी सम्पूर्ण राशि आरजीएचएस में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

लाभार्थी की श्रेणी

योजना राज्य के पेंशनर्स के लिए वरदान साबित हुई है जो चिकित्सा की राशि देने के पश्चात महीनों पुनर्भरण का इन्तजार कर रहे थे, साथ ही विधानसभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, सेवारत और सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों एवं जनवरी 2004 से पूर्व के सेवारत राज्य कर्मचारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत कर्मचारी तथा एक जनवरी 2004 से नियुक्त सेवारत राज्य कर्मियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत कर्मचारी, एक जनवरी 2004 से नियुक्त सेवानिवृत राज्य कर्मियों, स्वायत शासी संस्थाओं के सेवानिवृत कर्मियों, एवं एक जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनर्स को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है।

आरजीएचएस की सुविधा राज्य के बाहर भी

"परियोजना निदेशक, श्रीमती शिप्रा विक्रम के अनुसार आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत राज्य के 299 निजी चिकित्सालयों का अनुमोदन लाभार्थियों के हितार्थ किया जा चुका है। पात्र लाभार्थी अब राज्य के बाहर स्थिति निजी चिकित्सालयों में भी योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस कड़ी में नई दिल्ली एवं गुरूग्राम अवस्थित सुरभि अस्पताल, पार्क अस्पताल (तीन इकाईयों को) एवं सिग्नेचर अस्पताल को अनुमोदित कर दिया गया है। अहमदाबाद एवं अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों का अनुमोदन किया जाना प्रक्रियाधीन है। अब राज्य के बाहर रहने वाले राज्यकर्मियों के साथ ही शेष लाभार्थी भी राज्य के बाहर बेहतर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार में कठिनाई को देखते हुए प्राथमिकता के साथ एचसीजी अस्पताल, अहमदाबाद को शीघ्र योजना के दायरे में लाया जा रहा है। शासन की मंशानुरूप, आरजीएचएस कैशलेस, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है।

खेल और खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना

प्रदेश के चहुंमुखी विकास और व्यापक जनहित में योजनाओं और कार्यक्रमों की झड़ी लगाने वाली राज्य सरकार अपने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह संकल्प को सभी क्षेत्रों समान रूप से अपनाया है।

चाहे आधारभूत ढांचे के विकास और विस्तार की बात हो अथवा जरूरतमंदों के जेहन की पीड़ा समझकर उनके दुःख-सुख में पूरी मानवीय संवदेना अपनाते हुए राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में नवाचार किए हैं जिनसे आमजन के मन में यह आशा और विश्वास बना है कि 'राम के बाद यही राज है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भक्त नरसी मेहता के प्रिय भजन-''वैष्णव जन तो तैने कहिए, जे पीड़ पराई जाणै रै'' के मर्म को मन, वचन और कर्म से फलीभूत किया।'

प्रदेश में पिछले तीन सालों में जिस तरह सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, उद्योग-धन्धे आदि के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के साथ वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, महिला, किशोरी, बालिका, बालक और नौजवान आदि सभी वर्गों के लिए जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की सरिताएं बहा दी है।

जहां तक खेल, खेल के मैदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात है, राज्य सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप इस दिशा में खुले मन से खजाना खोलकर रख दिया है। इससे दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कस्बों, नगरों और महानगरों तक बाल खेल प्रतिभाओं से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन की धाक जमाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की पौबारह हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में खिलाड़ियों को ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर 50 लाख को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 30 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना सरकार की इस दिशा में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में नये उत्साह का संचार किया है।

प्रदेश में खेलकूद के इतिहास में खिलाड़ियों का मनोबल, साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे अनुपम हैं। इतना ही नहीं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 50 हजार रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 30 हजार रुपये दिये जा रहे हैं।

नारायणसिंह राठौड़
स्वतंत्र पत्रकार

राज्य सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप इस दिशा में खुले मन से खजाना खोलकर रख दिया है। इससे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कस्बों, नगरों और महानगरों तक बाल खेल प्रतिभाओं से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में अपने प्रदर्शन की धाक जमाने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की पौबारह हो गई है।

यह उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही यह राशि अधिक होने के साथ ही नई पीढ़ी की खेलकूद के प्रति अभिरूचि बढ़ाने वाली है।

अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में प्रदेश के ओलम्पिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेता और अर्जुन अवॉर्ड प्राप्त खिलाड़ियों को 220 वर्गमीटर भूखण्ड तथा पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 25 बीघा भूमि आवंटित की जाती है। यह पैकेज भी उत्साहवर्धक है।

राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियो के लिये टी.ए. और डी.ए. की राशि भी प्रति खिलाड़ी 300 एवं 500 रुपये से बढ़ाकर 600 एवं 1000 रुपये प्रति दिन कर दी गई है।

मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्माण के लिए विधायक-सांसद निधि, जन प्रतिनिधि, जन सहयोग और कॉरपोरेट सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। इसके लिए प्रदेश के 15 स्थानों के जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है। इससे एक तरफ मेजर ध्यानचन्द जैसे हमारे प्रेरक खेल हीरो का नाम खिलाड़ियों को उनके हॉकी के क्षेत्र में उनकी अपनी खेल तकनीकों का स्मरण कराते रहेंगे। दूसरी तरफ उनके जैसी मेहनत और लगन की भावना विकसित करने की प्रेरणा लेने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

कॉरपोरेट सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 100 एथलीटों का केम्प लगाकर 20 खिलाड़ियों का चयन कर उनको 3 वर्षों तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क ट्रेनिंग दिये जाने के साथ-साथ अन्य खर्चे वहन किये जायेंगें। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को चयन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार यह नवाचार भी महत्वपूर्ण है। इससे कॉरपोरेट

क्षेत्र भी प्रदेश में उच्च कोटि के खिलाड़ी तैयार करने में मददगार साबित होगा। यह मदद निरी सहायता नहीं होकर कॉरपोरेट जगत की सामाजिक सेवा और सामाजिक दायित्व का एक अंग है।

राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम 2019 खिलाड़ियों के हित में लागू किया है। इससे प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर इन नियमों के तहत सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जायेगा।

स्कूल गेम्स फैडरेशन इंडिया और अखिल भारतीय विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता के पदक विजेता भी इन नियमों के तहत शामिल हैं। राज्य सरकार ने 56 विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2 से 6 जनवरी 2020 तक राज्य खेल-2020 का अभूतपूर्व आयोजन किया गया। इसमें 18 खेलों में 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके पदक विजेताओं के लिए 1.25 करोड़ रुपये की ईनामी राशि का प्रावधान किया गया। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाये जायेंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा।

उपलब्धियां ही उपलब्धियां

वर्ष 2021 में अवनी लेखरा, (पैरा शूटिंग) एवं कृष्णा नागर (पैरा बैडमिन्टन) को भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेजर ध्यानचंद (खेल रत्न) अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को नियमानुसार 23 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है।

इसी प्रकार विभिन्न संस्थाओं को प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए विगत तीन वर्षों में नियमानुसार राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान के रूप में 1 करोड़ 86 लाख 57 हजार रुपये से अधिक राशि का वितरण किया गया।

प्रदेश में कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, हॉकी एवं शूटिंगबॉल 6 खेलों में बालक वर्ग और खो-खो बालिका वर्ग के राजस्थान ग्रामीण ऑलम्पिक खेल, 2021 ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के लगभग 24 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस प्रकार का कीर्तिमान रचने वाला राजस्थान प्रदेश पूरे विश्व में पहला होगा।

राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन तैयार कर लिया गया है।

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में बिना पारी (आउट ऑफ टर्न) नियुक्ति के नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाते हुए लागू किया गया है।

राज्य सरकार का यह निर्णय खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सराहनीय है। इससे खेलों की महत्ता बढ़ेगी। युवा इस ओर भी आकृष्ट होंगे।

बिना पारी (आउट ऑफ टर्न) नियुक्ति के नियमों के अन्तर्गत 182 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें ए वर्ग में 13, बी वर्ग में 23 एवं सी वर्ग में 146 कुल 182 खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 22 खिलाड़ियों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खेल और खिलाड़ियों के लिए आधारभूत सुविधाएं

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में 15 करोड़ 30 लाख रुपये लागत से हाई परफोरमेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का कार्य पूर्ण कर लिया है। साथ ही उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में शेड निर्माण कार्य और सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्थेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ का रिनोवेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

इसी तरह डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी एवं जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी और सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में रेजीडेंटल स्पोर्ट्स स्कूल प्रारम्भ कर दिया गया है।

गुवाहाटी (आसाम) में 9 से 22 जनवरी, 2020 तक आयोजित हुए तीसरे इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान की ओर से 16 खेलों में 219 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उस प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 24 रजत, 12 कांस्य सहित कुल 51 पदक अर्जित करते हुए देश में 11वां स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों को अवसर और उपलब्धियां

प्रदेश के तीन खिलाड़ियों सुश्री अपूर्वी चंदेला, श्री दिव्यांश सिंह पंवार और सुश्री भावना जाट ने 2020 टोक्यो ओलम्पिक में भाग लिया।

इसी तरह 6 पैरा खिलाड़ियों श्री सुंदर सिंह गुर्जर, श्री देवेन्द्र झांझड़िया, श्री संदीप सिंह मान, श्री कृष्णा नागर, सुश्री अवनी लेखरा और श्री श्याम सुंदर स्वामी ने 2020 टोक्यो पैरा-ओलम्पिक में भाग लिया।

प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि टोक्यो पैरा-ऑलम्पिक गेम्स 2020 में प्रदेश के चार खिलाड़ियों अवनी लेखरा ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक, कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक, देवेन्द्र झांझडिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

इस प्रकार प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों में नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में उच्चकोटि के खिलाड़ी उभरकर आगे आएंगे और प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करने में सफल होंगे।

हारेगा कोरोना, फिर जीतेगा राजस्थान

हेतप्रकाश व्यास
सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

विदेशों में तबाही मचाने के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने राजस्थान में पैर पसारने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा की अगुवाई में चिकित्सा विभाग पूरी तरह सजग और सतर्क है। विभाग द्वारा संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की हरसंभव कोशिश की जा रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में राजस्थान के कोरोना प्रबंधन को देश भर में सराहा गया। संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है।

वैक्सीनेशन पर सर्वाधिक जोर

विश्व स्वास्थ्य संगठन व अनेक मेडिकल विश्वविद्यालयों में हो रहे शोधों के अनुसार कोरोना को नियंत्रित करने में वैक्सीनेशन सबसे असरदार टूल साबित हुआ है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वैक्सीनेशन पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया। स्वयं चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहते नजर आए कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों पर सख्ती की जा सकती है। इसी का परिणाम रहा कि राज्य में अब तक 95 फीसदी से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज व 77 प्रतिशत से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं।

वैक्सीनेशन के प्रति किशोरों और बुजुर्गों ने भी दिखाया जोश

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के आग्रह पर केंद्र सरकार ने 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग से किशोर-किशोरियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन, हेल्थ वर्कर व 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाए जाने लगे। राज्य सरकार ने दोनों वर्गों के लिए व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप, साइट सेशन प्रारंभ किए। नतीजा यह रहा कि अब तक 50 प्रतिशत से अधिक किशोर-किशोरी व 3 लाख से अधिक हेल्थ, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 साल से अधिक आयु वर्ग का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य में इस वर्ग के लाभार्थियों की संख्या लगभग 24.15 लाख है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी 5.17, फ्रन्टलाइन कार्यकर्ता 6.48 और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगग्रस्त वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 12.50 लाख है। इसी तरह प्रदेश में 15 से 18 साल की आयु के किशोरों की संख्या लगभग 54 लाख है।

ऑक्सीजन के मामले में राजस्थान बना आत्मनिर्भर

चिकित्सा विभाग कोरोना की तीसरी लहर से आमजन के बचाव की तैयारियां पूरी सजगता से कर रहा है। बकौल चिकित्सा मंत्री प्रदेश में कुल 532 अक्सीजन प्लांट की तुलना में 473 से

ज्यादा प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही 40 हजार ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में तुरंत ऑक्सीजन एवं भिवाड़ी प्लांट को मिलाकर राज्य की कुल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1050 मेट्रिक टन हो गई है। अब प्रदेश मेडिकल ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है।

तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी तैयारियां पूरी

तीसरी लहर से मुकाबले के लिए विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा कहते हैं कि राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 50 हजार सामान्य, 28 हजार ऑक्सीजन, 6 हजार आईसीयू एवं 1500 नीकू-पीकू बेड उपलब्ध हैं। राज्य के विभिन्न पीएचसी, सीएससी एवं एसडीएच में से 332 चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित कर वहां एचडीयू बेड विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 123 चिकित्सा संस्थानों पर 560 एचडीयू बेड विकसित किए जा चुके हैं, शेष पर कार्य जारी है। गांवों में स्थित सामुदायिक केंद्रों पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि ग्रामीणों को शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़े और शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पर दबाव भी कम रहे।

चिकित्सा संस्थानों में एक महीने की दवा का स्टॉक

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा इन्डीकेडेट 8 महत्वपूर्ण दवाइयों में से 7 दवाइयों का पर्याप्त बफर स्टॉक (तीस दिन की आवश्यकतानुसार) राज्य में उपलब्ध है। टोसीलीजुनाब की खरीद भारत सरकार द्वारा आवंटित कोटे के अनुसार की जाती है। आवंटित कोटे की खरीद की जा चुकी है। अतिरिक्त आवंटित होने पर क्रय की जाएगी। चिकित्सा मंत्री के अनुसार संक्रमण से बचाव के दौरान जरूरत पड़ने पर गांव-गांव तक मेडिसिन किट पहुंचाई जाएंगी। किसी भी चिकित्सा संस्थान में दवाओं, इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश की पॉजीटिविटी दर देश की साप्ताहिक दर से भी कम

भले ही राज्य में कोविड-19 के कुल एक्टिव कैसेज 45 हजार 565 हैं लेकिन बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के चलते प्रदेश की साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर देश की साप्ताहिक दर से खासी कम है। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव कैसेज में से लगभग 98 प्रतिशत होम आइसोलेशन में है एवं जबकि 2 प्रतिशत अस्पतालों में भर्ती हैं। राज्य में ओमिक्रोन के 529 मरीज हैं।

जिनोम सीक्वेंसिंग में पॉजिटिव मरीजों में से लगभग 92 प्रतिशत ओमिक्रोन के ही पाए गए हैं। राज्य में प्रतिदिन लगभग 63 हजार सैम्पल लिये जा रहे हैं, जिसकी संख्या को आने वाले दिनों में 1 लाख तक ले जाया जाएगा।

रेपिड एंटीजन से जांच की दर 50 रुपए की निर्धारित

राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जांचें करवाने के लिए निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की रेपिड एंटीजन जांच की अधिकतम दर 50 रुपये प्रति जांच (जीएसटी व सभी कर सहित) निर्धारित की है। आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित कमेटी के प्रस्तावानुसार यह दर निर्धारित की है। किसी भी स्तर पर ज्यादा कीमतें वसूलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

चलाएंगे 'कोविड वैक्सीनेशन वाहन'

प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और वंचित लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभाग द्वारा 'कोविड वैक्सीनेशन वाहन' चलाए जाएंगे। इन वाहनों में बैनर, पंपलेट और माइकिंग की सुविधा होगी। ये वाहन उन क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे जहां टीकाकरण का प्रतिशत कम है या जागरूकता का अभाव है। वाहन के साथ जा रही टीमें स्कूल, हॉस्टल, भीड़भाड़ वाले बाजार, हाट व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी घूमकर लोगों को वैक्सीनेशन के महत्व को समझाएगी और इसके फायदे गिनाएगी।

मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा

चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा के अनुसार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। छह विभाग की टीमें मिलकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। प्रदेश भर में अब तक सैकड़ों स्थलों पर निरीक्षण कर मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है।

15 से 18 वर्ष आयुवर्ग का कोविड वैक्सीनेशन

ओमिक्रोन के खतरे से बचाव के लिए सुनिश्चित होगा शत-प्रतिशत टीकाकरण

ओमिक्रोन वैरिएंट के रूप में देश और दुनिया के सामने अस्तित्व का नया संकट आ खड़ा हुआ है। इस खतरे से मानव जाति की रक्षा के लिए जरूरी है कि जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगे 6 माह से अधिक का समय हो गया है, ऐसे सभी लोगों को जरूरत के अनुसार बूस्टर डोज लगाई जाए तथा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का भी जल्द निःशुल्क टीकाकरण शुरू हो। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से अब तक वैक्सीनेशन का शानदार प्रबंधन किया गया है आगे भी उसी भावना के साथ गांव-ढाणी तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना है। राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार

में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के निःशुल्क टीकाकरण का शुभारम्भ हुआ। कोविड की प्रथम डोज लगवाने वाली 5 किशोरियों की हौसला अफजाई कर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उन्हें चॉकलेट भेंट की। कोविड महामारी के खतरे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है।

पहली एवं दूसरी घातक लहर झेलने के बाद अब ओमिक्रोन वैरिएंट के रूप में नया खतरा सामने है। दुनिया के अधिकतर देशों में पहुंच चुके ओमिक्रोन वैरिएंट के कारण तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके सुनामी का रूप लेने की चेतावनी दी है। कोविड-19 के संबंध में पूर्व अनुभवों से यह बात सुस्पष्ट है कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही देश व प्रदेश में बहुत सी अमूल्य जानें बचाई जा सकी हैं इसलिए इस खतरे की गंभीरता से समझकर बड़ों से लेकर बच्चों तक का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। दुनिया के कई मुल्कों में बूस्टर डोज लग रही है और क्यूबा जैसे देश में तो दो साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है।

देश में भी 15 साल से कम आयु के बच्चों के निःशुल्क टीकाकरण तथा सभी को बूस्टर डोज के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार देशवासियों की जीवन रक्षा के लिए जल्द निर्णय किया जाना जरूरी है। ओमिक्रोन वैरिएंट से फैलते संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज तथा 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों का टीकाकरण शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था। अब देश में 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है।

वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। प्रदेश में लक्षित आबादी के करीब 91.50 प्रतिशत अर्थात 4 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 75 प्रतिशत से अधिक अर्थात 3 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार करीब 8 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस मामले में प्रदेश राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे हैं।

बीते दो साल से कोविड की विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने सुशासन के लिए पूरा प्रयास किया। हर वर्ग के कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश के 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 123 सरकारी कॉलेज खोले गए हैं। जिनमें 33 महिला महाविद्यालय हैं। जिन विद्यालयों की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होंगी वहां महाविद्यालय खोला जाएगा।

राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार को भी कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सभी कोविड प्रोटोकॉल तथा कोविड गाइड लाइन की अक्षरशः पालना करें। 31 जनवरी तक सभी पात्र लोगों को अनिवार्य रूप से दूसरी डोज लगाने के कार्य को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहा है।

चिकित्सा मंत्री ने लगवाई प्रिकॉशन डोज आमजन से की वैक्सीनेशन की अपील

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने एसएमएस अस्पताल के आईडीएच में कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज (तीसरी डोज) लगवाई।

चिकित्सा मंत्री के अनुसार वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना जैसी महामारी को मात दी जा सकती है। वैक्सीनेशन के प्रति आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य में अब तक 93 प्रतिशत से अधिक आबादी को कोविड की प्रथम डोज व इनमे से 76 प्रतिशत लोगों को द्वितीय डोज लग चुकी है। प्रदेश के 40 प्रतिशत से अधिक 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों को प्रथम डोज लग चुकी है।

अश्वगंधा

तुलसी

कालमेघ

गिलोय

घर-घर औषधि योजना

आगाज अच्छा, अंजाम भी अच्छा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दो लहरों के बाद कोरोना का नया वेरिएंट सामने है। बताते है कोरोना का कहर बीमारों पर अधिक प्रहार कर रहा है। ऐसे में वैकल्पिक उपाय के रूप में हम अपने उन औषधीय पौधों को भूल रहे है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से घर बैठे बचाते हैं। राजस्थान सरकार ने गत मानसून में घर-घर औषधीय पौधे पहुंचाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को त्वरित रूप से अमलीजामा पहनाया। राजस्थान वन विभाग की नर्सरी हजारों औषधीय पौधे विकसित कर रही हैं, जिन्हें पांच वर्षों में घर-घर औषधि योजना के तहत लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अंतर्गत इम्युनिटी बढ़ाने हेतु बहु-उपयोगी औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा वन विभाग की 565 पौधाशालाओं में तैयार किये जा रहे हैं।

बालमुकुन्द ओझा
संयुक्त निदेशक (से.नि.)

कोरोना में कारगर

कोरोना महामारी से निपटने के लिए वर्तमान सरकार की यह अनूठी और अभिनव पहल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। अक्सर देखा जाता है जनता से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं बड़े प्रचार-प्रसार के साथ शुरू अवश्य होती हैं मगर धरातल पर उनका क्रियान्वयन सुचारु नहीं होने से वे जल्द ही दम तोड़ने लगती हैं। घर-घर औषधि योजना का आगाज तो अच्छा है। अब यह हम जनता जनार्दन पर निर्भर करता है कि इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और विभिन्न बीमारियों से लड़ने की अपनी क्षमता विकसित करें। सरकार

हरसंभव प्रयास और सहयोग कर रही है। सभी को आगे आकर प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी।

घर-घर औषधि योजना के तहत अब तक 4.67 करोड़ औषधीय पौधे सम्पूर्ण प्रदेश में वितरित किये जा चुके हैं। एक अगस्त, 2021 से प्रारम्भ हुई इस अति महत्वाकांशी योजना में 1.26 करोड़ परिवारों को पांच वर्षों में तीन बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के 2-2 पौधे, कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे।

प्राण वायु देते है

हमारे बड़े बुजुर्ग हमें औषधीय पौधों के फायदे बताते हैं। बहुत से बड़े बुजुर्ग आज भी अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करते और अपने बेहतर स्वास्थ्य के राज की बातें बताते नहीं थकते मगर हम अपनी दौड़ भरी लाइफ स्टाइल में स्वस्थ जीवन के मंत्र की बातें सुनना पसंद नहीं करते। फलस्वरूप विभिन्न शारीरिक रोगों को भोगते हुए जैसे-तैसे अपने जीवन की गाड़ी को हांकते है। यदि हम कोरोना जैसे संक्रमण का मुकाबला करने के लिए अपने घरों पर औषधीय पौधे लगाएं तो ये हमें प्राण वायु प्रदान करने के साथ ही साथ स्वस्थ जीवन की राह भी दिखाएंगे।

पेड़-पौधे हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। प्राचीन काल में मानव ने तरह-तरह के पेड़-पौधों की खोज कर खुद को निरोगी रखा। मानव सभ्यता के विकास के साथ विज्ञान ने हमें चिकित्सा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, इसमें दो राय नहीं है मगर स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों की महत्ता कभी कम नहीं हुई। भारत में औषधीय गुण वाले असंख्य पेड़-पौधे हैं। भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इनके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं।

रामायण में संजीवनी बूटी की चर्चा आज भी घर-घर में सुनी जा सकती है। बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयों में आज भी औषधीय पौधों का मिश्रण किया जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, बीपी, शुगर, उलटी-दस्त जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों से उबरने में ये औषधीय पौधे महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यदि इन पेड़ पौधों का हम उचित रखरखाव कर विभिन्न रोगों के इलाज में सही ढंग से उपयोग करें तो ये हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बेहद लाभदायक हो सकते हैं।

औषधीय पौधे हमारी धरोहर

औषधीय एवं सुरभित पौधे हमारी धरोहर हैं जिनका वैश्विक महत्व है। विश्व में असंख्य औषधीय एवं सुरभित पौधों की प्रजातियां हैं। उनमें से अनेक पौधों का उपयोग हम विभिन्न कारणों से करते हैं और अनेक के बारे में अभी हमारा ज्ञान सीमित है। भारत के रेड डाटा

बुक में 427 संकटग्रस्त पौधों के नाम दर्ज हैं, इनमें से 28 लुप्त, 124 संकटग्रस्त, 81 नाजुक दशा में, 100 दुर्लभ तथा अन्य पौधे हैं। भारत के पहाड़ी और जंगली इलाकों में उपलब्ध तीन सौ से अधिक औषधीय वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर इनके संरक्षण की दिशा में पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले वर्षों में कई वनस्पतियां विलुप्त हो जाएंगी।

बहुत सी अंग्रेजी दवाइयों के साथ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा जैसी पद्धतियों में औषधीय पौधों का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। भारत सरकार के ऑल इण्डिया को-ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एथनो-बायोलॉजी द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि लगभग 8 हजार पेड़-पौधे का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में लगभग दो हजार, सिद्धा में लगभग एक हजार और यूनानी में लगभग 750 पौधे ऐसे है जिनका उपयोग विभिन्न दवाओं के निर्माण में किया जाता है।

बहुगुणकारी है

हमारे विभिन्न ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में हजारों से नुस्खे बताये गए है जो औषधीय पौधों से निकले है। हमारे देश में आज भी लाखों लोग इन नुस्खों का उपयोग करते है। नीम, तुलसी, बेंग साग, ब्राम्ही, हल्दी, चन्दन, चिरायता, अडूसारू, सदाबहार, गुलाब, सहिजन, हडजोरा, करीपत्ता, लहसून, एलोवीरा लेवेंडर, जीरा, पुदीना, गिलोय, सूरजमुखी, पीपल, आक, बरगद, आंवला, गुग्गल, अदरख, नीम्बू, पत्थरचूर, शतावर, अजवायन, चुकंदर, चिरचिटी, कुल्थी, घृतकुमारी, करेला, पिपली, मेथी, पुनर्नवा, मदन मस्त, पिपली, चंपा, रजनीगंधा, श्वेत अपराजिता, सर्पगन्धा, अशोक और वलाक आदि औषधीय पौधों में से बहुत से भी है जो घरों में लगाए जा सकते है। इनमें बहुत सी प्रजातियां अब लुप्तप्रायः हैं।

आवश्यकता इस बात की है इन बहु गुणकारी औषधीय पौधों के विकास की योजनाएं बनाकर आम आदमी को इनके प्रयोग और उपयोग की जानकारी दी जाएं।

राजस्थान सुजस 2022

छाया : सविता चौहान, अमित सारस्वत

जनवरी

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1*
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

अवकाश : 09 गुरू गोबिन्द सिंह जयंती
26 गणतंत्र दिवस

ऐच्छिक अवकाश
01 नव वर्ष

फरवरी

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26*
27	28					

ऐच्छिक अवकाश
07 देवनारायण, 14 विश्वकर्मा, 15 स्वामी रामचरण,
16 गुरु रविदास, 23 गाडगे महाराज, 26 महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती

मार्च

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18*	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अवकाश : 01 महाशिवरात्रि, 17 होलिका दहन
18 धूलण्डी

ऐच्छिक अवकाश
18 शब-ए-बारात

अप्रेल

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14*	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

अवकाश : 02 चेटीचण्ड, 10 रामनवमी,
14 डॉ. अम्बेडकर जयंती,
14 श्री महावीर जयंती, 15 गुड फ्राईडे

ऐच्छिक अवकाश : 11 महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती,
14 वैशाखी, 27 सैन जयंती, 29 जुमातुल विदा

मई

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

अवकाश : 03 परशुराम जयंती
03 ईदुलफितर (चांद से)

ऐच्छिक अवकाश
16 बुद्ध पूर्णिमा

जून

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

अवकाश : 02 महाराणा प्रताप जयंती

जुलाई

S	M	T	W	T	F	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

अवकाश : 10 ईदुलजुहा

ऐच्छिक अवकाश
13 गुरू पूर्णिमा

अगस्त

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

अवकाश : 09 विश्व आदिवासी दिवस, 09 मोहर्रम (चांद से),
11 रक्षा बंधन, 15 स्वतंत्रता दिवस, 19 श्री कृष्ण जन्माष्टमी

ऐच्छिक अवकाश
18 थदड़ी, 31 गणेश चतुर्थी

सितम्बर

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

अवकाश : 05 रामदेव जयंती, तेजा दशमी
एवं खेजड़ली शहीद दिवस, 26 नवरात्रा स्थापना

ऐच्छिक अवकाश :
01 संवतसरी, 09 अनन्त चतुर्दशी

अक्टूबर

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

अवकाश : 02 महात्मा गांधी जयंती, 03 दुर्गाष्टमी,
05 विजय दशमी, 09 बारावफात (चांद से),
24 दीपावली, 25 गोवर्धन पूजा, 26 भैया दूज

ऐच्छिक अवकाश :
04 महानवमी, 13 करवाचौथ

नवम्बर

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

अवकाश : 08 गुरुनानक जयंती

दिसम्बर

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18*	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

अवकाश : 25 क्रिसमस डे
29 गुरुगोबिन्द सिंह जयंती

ऐच्छिक अवकाश
18 श्री पार्श्वनाथ जयंती

ढूंढाड़ के महाराज की तुक्कल की उड़ान ने

पतंगबाजी को दिया "उन्मुक्त गगन"

जितेन्द्र सिंह शेखावत
वरिष्ठ पत्रकार

मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी ने धर्म और जाति की दीवारों को तोड़कर सांप्रदायिक सद्भाव की डोर को और मजबूत किया है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह (1833- 1880) ने अपनी लखनऊ की यात्रा के दौरान वहां पतगें उड़ती देखी थी। वे वहां के मुसलमान पतंगसाज परिवारों को जयपुर ले लाए और यहां पर बसा दिया। बाद में लखनऊ, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और दिल्ली आदि से भी पतंग कारीगर जयपुर में आकर बसे। उन मुसलमान पतंगसाजों ने अपने हुनर से यहां की पतंगों को जग विख्यात कर दिया।

सख्तखंडीय सिटी पैलेस की छत से सवाई राम सिंह ने बड़ी पतंग यानी तुक्कल को उड़ाना शुरू किया था। वे मोटी डोर से तुक्कल उड़ाते। तेज हवा में उनकी तुक्कल टूट जाती तब घुड़सवार उसे वापस लाते। यहां के लोग भी राजा की टूटी पतंग को सम्मान के साथ सिटी पैलेस में वापस लाते तब उन्हें इनाम दिया जाता था। चन्द्र महल की एक कोठरी में लकड़ी के बक्से में रखे डोर के चरखे आज भी सुरक्षित हैं। सवाई राम सिंह शिव भक्त भी थे तब उनके समय में शिवरात्रि पर भी पतगें उड़ाई जाती थी। सवाई जय सिंह के स्थापित छत्तीस कारखानों में एक पतंग का कारखाना भी स्थापित किया गया। मकर संक्रांति पर पूर्व राज परिवार की ओर से चांदी सोने की घुंघरू जड़ी पतंगें, देशी घी की फीणी, तिल के लड्डू आदि राधा गोविंददेव जी व अन्य मंदिरों में भेजे जाते थे।

शुरू हुए पतंग दंगल

पतंगबाजी ने सन् 1920 के बाद जोर पकड़ा । तब जल महल और लाल डूंगरी मैदान पर पतंगों के दंगल होने लगे। सन् 1961 में कन्हैयालाल तिवारी के संयोजन में जल महल के मैदान में राष्ट्रीय स्तर के दंगल शुरू हुए। इनमें दिल्ली व बरेली की टीमों के मिर्जा नन्हा बैग और सुकन उस्ताद आदि ने अपना जोर आजमाया। सन् 1974 में काइट फ्लाइंग क्लब ने दंगल करवाया। जिसमें देश की 68 टीमों ने भाग लिया था। अलीमुद्दीन, बाबू पहलवान, अब्दुल शकूर उर्फ टुन्नी भाई ने साफ-सुथरे पेच लड़ाए। 19 मार्च 1978 को हुए दंगलों में दिल्ली का नेशनल फाइट क्लब पहले स्थान पर रहा। सवाई जयसिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में भी पतंग के दंगल हुए। पतंगबाजी के रंग में डूबे पूरे ढूंढाड़ में अब भी कानोता की ढूंढ नदी के मैदान में दंगल होते हैं। पतंग डोर व्यवसाय से रोजगार भी बढ़ा है। रामगंज और घाटगेट इलाके में पतंग वालों के मोहल्लों में बारह महीनों पतगें बनाने का काम चलता है। जयपुर की बनी पतगें अहमदाबाद आदि शहरों में जाने लगी हैं। यहां की पतगं के पेच साफ-सुथरे होने के कारण जयपुर की पतगंबाजी को देश में एक नई पहचान मिली है।

संक्रांति पर ज्योतिष विद्वान बताते थे भविष्यफल

जयपुर के ज्योतिष विद्वान मकर संक्रांति को आपस में मंत्रणा के बाद राज्य के वार्षिक भविष्यफल की घोषणा करते थे। इस दिन ''जय विनोदी'' पंचांग का विमोचन होता था। सारे विद्वान चांदपोल बाजार में गोविंद राजियों के रास्ते के नुक्कड़ पर शाम को एकत्रित होते और ग्रह-नक्षत्र का अध्ययन करने के बाद वहां मौजूद आम जनता को आने वाले साल के भविष्य की जानकारी देते थे। सवाई जयसिंह के समय विद्वान पंडित केवलराम ने जय विनोदी पंचांग बनाने के बाद सामूहिक भविष्यवाणी बताने की इस परंपरा को शुरू किया था।

उस जमाने में मकर संक्रांति को मंदिरों और चबूतरों पर चलने वाली चटशाला के शिक्षक जोशीजी विद्यार्थियों के साथ भजन-कीर्तन करते थे। शहर के नर-नारी सुबह चार बजे से ही गलता तीर्थ में पुण्य स्नान के लिए पैदल निकल पड़ते। गलता पहाड़ी पर सूर्य मंदिर में दर्शन करने के बाद दान-पुण्य करते हैं। संक्रांति पर सुख समृद्धि की कामना से फीणी आदि तेरह वस्तुओं का बायना भी सुहागनें भेंट करती हैं।

महाराजा काली पोशाक पहन तुलादान करते थे

संक्रांति को महाराजा भी कुछ देर काली पोशाक पहनकर छाया व तुलादान करते थे। मकर संक्रांति पर जानवरों का वध करने पर कड़ा प्रतिबंध रहता। एक बार जयपुर की संक्रांति पर ग्वालियर महाराजा जियाजी राव आए, तब उनके सम्मान में संगीत की महफिल हुई थी। पुरानी राजधानी आमेर में भी पतंग उड़ाने का महाकवि बिहारी ने उल्लेख किया है। इसके अलावा सवाई जयसिंह के कवि बखत राम ने बुद्धि विलास में ''वस्त्रागार बुनकर वकरसाज, कहूं बेचत गुडी पतंग बाज से'' वर्णन किया है।

सवाई राम सिंह ने एक संक्रांति पर 25 लाख रुपए से सूद सदावर्त स्थापित कर उस रकम के ब्याज से रोजाना गरीबों को भोजन बांटने का सिलसिला शुरू किया था। वर्ष 1938 की सक्रांति 9 जनवरी गुरुवार को और सन् 1910 में 13 जनवरी को संक्रांति थी। सन् 1780 में 11 जनवरी को आई संक्रांति पर सवाई प्रतापसिंह ने तुलादान किया। सन् 1910 में 13 जनवरी की संक्रांति को सवाई माधोसिंह ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया और पांच हजार गरीबों को भोजन कराया। संक्रांति के दूसरे दिन भिंडों का रास्ता स्थित रबड़ की टूटी पर गालीबाजी के अखाड़े जमते थे।

उत्तरायण 22 दिसम्बर को, मकर संक्रान्ति 14 जनवरी को क्यों ?

पृथ्वी के डगमगाने से 72 वर्ष में एक डिग्री बढ जाता है अयनांश

उत्तरायण का आधार ट्रॉपिकल ईयर और मकर संक्रान्ति का आधार नक्षत्र वर्ष

सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का त्योहार मकर संक्रान्ति के रूप में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ? जबकि खगोलीय रूप से सूर्य 22 दिसम्बर को ही उत्तरायण हो चुका होता है और ट्रॉपिकल यानि सायन राशिचक्र के अनुसार मकर राशि में प्रवेश भी कर चुका होता है।

डॉ. रजनीश शर्मा
उप निदेशक

उत्तरायण या दक्षिणायन धरती के अक्षीय झुकाव की देन है। यही कारण है कि वर्ष के दौरान सूर्य कर्क से मकर रेखा तक डोलता प्रतीत होता है। सूर्य वास्तव में 22 दिसम्बर को ही मकर रेखा पर अपने दक्षिणतम अक्षांश पर पहुंच उत्तर को गति प्रारम्भ करता है यानि उत्तरायण हो जाता है। इसी तरह 21 जून को सूर्य अपने उत्तरतम अक्षांश (कर्क रेखा) पर पहुंच दक्षिण को गति प्रारम्भ करता है अर्थात दक्षिणायन हो जाता है। लेकिन मकर संक्रांति 22 दिसम्बर को नहीं, 14 जनवरी को मनाई जाती है। दरअसल, ऐसा नक्षत्र वर्ष (साइडेरियल ईयर) एवं ट्रॉपिकल वर्ष के अनुसार वैदिक पद्धति की निरयण और सायन नामक दो प्रकार की गणनाओं में अन्तर के कारण होता है जिसे अयनांश के द्वारा इंगित किया जाता है। करीब 300 ईस्वी के आस-पास निरयन और सायन पद्धतियों में अन्तर नहीं था। धरती के अपने अक्ष पर घूमने से दिन-रात और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से ऋतुएं बनती हैं। लेकिन धरती की एक तीसरी गति भी है जिसमें धरती अपने अक्ष पर एक डोलते हुए लट्टू के समान डगमगाती हुई 26000 वर्ष में एक चक्र पूरा करती है। यह है धरती के अक्ष का अग्रगमन (Axial Precession)। हर वर्ष 21 मार्च व 23 सितम्बर को सूर्य खगोलीय विषुवत रेखा पर स्थित क्रमशः बसन्त विषुव बिन्दु व शरद विषुव बिन्दु पर होता है। पृथ्वी के भ्रमण एवं गतियों पर आधारित होने के कारण ट्रॉपिकल कलैण्डर को मौसम से जोड़ा जाता है। 21 मार्च (बसन्त विषुव), 21 जून (ग्रीष्म अयनांत), 23 सितम्बर (शरद विषुव) और 22 दिसम्बर (शीत अयनांत), बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के संकेतक हैं।

सायन काल गणना बसन्त विषुव बिन्दु से ही शुरू होती है। जबकी भारतीय नक्षत्र वर्ष सुदूर नक्षत्रों पर आधारित होने के कारण इसमें विचलन नहीं होता और निरयण काल गणना में यह शुरुआती बिन्दु अपने 1700 साल पुराने जगह पर ही निश्चित है। अर्थात एक साइडेरियल ईयर मेष राशि में सूर्य के प्रवेश से साथ प्रारम्भ होकर पुनः वहीं पहुंचने पर पूरा होता है। जबकि वर्ष दर वर्ष बसन्त विषुव बिन्दु धीरे-धीरे अक्षीय अग्रगमन के कारण पश्चिम की ओर खिसकता जाता है 21 मार्च (बसन्त विषुव बिन्दु) से आरम्भ होने वाला ट्रॉपिकल वर्ष अपने आरम्भ बिन्दु से पहले ही पूरा हो जाता है। फलतः सायन व निरयन पद्धति (साइडेरियल व ट्रॉपिकल वर्ष) का आपसी अन्तर बढ़ता जाता है। 72 वर्ष में यह अंतर एक डिग्री या एक दिवस का हो जाता है। इस प्रकार हर 72 वर्ष में दोनों पद्धति में मकर संक्रान्ति का अन्तर एक दिन और बढ़ जाता है। यह अन्तर ही अयनांश है जो वर्तमान में 24 डिग्री हो चुका है। इसीलिए ट्रॉपिकल सोलर वर्ष के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी से 24 दिन पूर्व ही हो जाता है, जबकि निरयन पद्धति के राशि चक्र में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को होता है। करीब 700 साल बाद निरायन मकर संक्रान्ति 24 जनवरी को मनाई जाएगी और हजारों साल बाद यह त्यौहार सर्दियों के बजाय गर्मियों में आया करेगा।

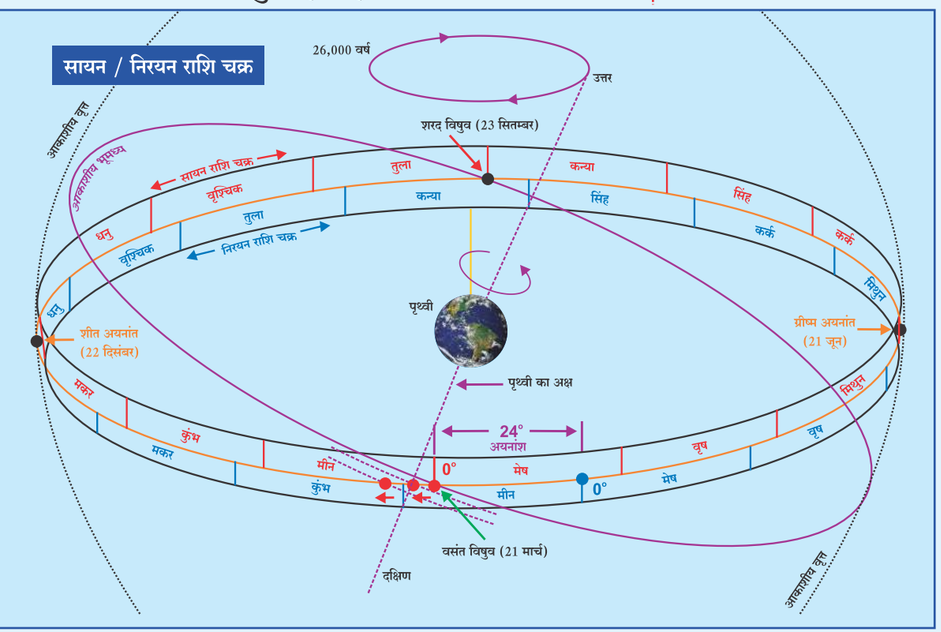

निरयन एवं सायन पद्धति के अनुसार सूर्य का राशि प्रवेश

राशि	निरयन	सायन
मेष	अप्रेल 14	मार्च 21
वृष	मई 15	अप्रेल 20
मिथुन	जून 15	मई 21
कर्क	जुलाई 16	जून 21
सिंह	अगस्त 17	जुलाई 22
कन्या	सितम्बर 17	अगस्त 23
तुला	अक्टूबर 18	सितम्बर 23
वृश्चिक	नवम्बर 16	अक्टूबर 23
धनु	दिसम्बर 16	नवम्बर 22
मकर	**जनवरी 14**	**दिसम्बर 21**
कुंभ	फरवरी 20	जनवरी 20
मीन	मार्च 15	फरवरी 28

Axial Precession (26,000 Years)

सायन पद्धति के साथ खास बात यह है कि पृथ्वी की अक्षीय गति (axial precession) के कारण राशियों के स्थान में परिवर्तन आता है और सायन गणना पद्धति को मानने वाले पाश्चात्य जन्मकुण्डली में रशियों का स्थान बदल जाता है। इसीलिए नासा के शोधकर्ता लॉरी कैंटिलो ने बीबीसी से एक वार्ता में कहा था कि, ''हमने लोगों की राशि नहीं बदली, हमने केवल गणना की है।'' नासा ने बताया कि पृथ्वी की धुरी बदल जाने से नक्षत्र अब उसी स्थान पर नहीं हैं जहां वे हजारों साल पहले थे।

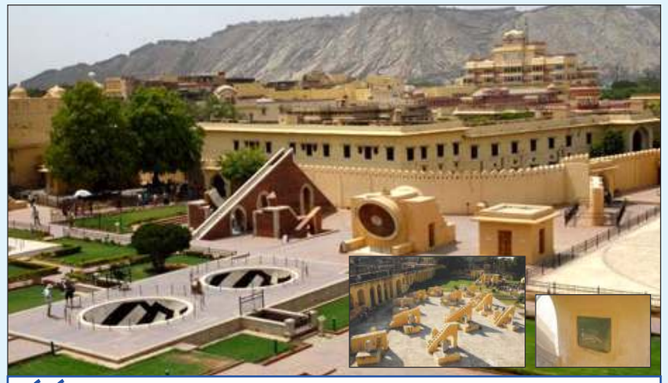

"वैदिक ज्योतिष की गणनाएं नक्षत्रों के वास्तविक प्रेक्षण पर आधारित है। इसलिए इसमें अयन का विचार नहीं किया जाता। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से देखने पर सूर्य जिस नक्षत्र राशि से गुजरता दिखाई देता है, भारतीय ज्योतिष में उसी के अनुरूप गणनाएं की जाती हैं। इसीलिये मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। भारतीय खगोल शास्त्र में 27 नक्षत्र और नौ ग्रह, हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं और विभिन्न नक्षत्रों के नौ चरणों को मिलाकर एक राशि का निर्माण होता है। **डॉ. अमित व्यास,** एस्ट्रोलॉजी के जानकार

"जयपुर में खगोलीय गणनाओं और प्रेक्षणों की विरासत तीन सदियों पुरानी है। जयपुर स्थित राष्ट्रीय स्मारक प्रसिद्ध जंतर-मंतर हमारी इस महत्वपूर्ण पैतृक विरासत के अतीत का जीवंत प्रतीक है।

यहां स्थित प्रसिद्ध ''सम्राट यंत्र'' के नीचे स्थित ''षष्ठांष यंत्र'' क्षितिज के ऊपर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई को बताता है। इसे देखकर कोई भी आसानी से सत्यापित कर सकता है कि सायन मकर संक्रान्ति वाले दिन (22 दिसम्बर) को दोपहर का सूरज क्षितिज पर अपनी सबसे निचली ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यही शीत अयनांत है। इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाता है और इसके 24 दिन बाद यानी 14 जनवरी को सूरज इस यंत्र पर कुछ ऊंचाई हासिल कर चुका होता है। इन दो अलग-अलग दिनों में सूर्य की स्थितियों के बीच देशांतर में 24 डिग्री का अंतर ''राशि वलय यंत्र'' में स्थित मकर राशि के यंत्र का उपयोग कर निर्धारित किया जा सकता है। ● **संदीप भट्टाचार्य**
उप निदेशक, बिड़ला तारामण्डल, जयपुर

"ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग"

● मारवाड़ में कच्ची घाणी से तेल निकालने की परम्परा आज भी जारी है ● मारवाड़ की तिल्ली का तेल व इससे बनने वाले व्यंजन इन दिनों बिखेर रहे सुगन्ध

नरेंद्रसिंह जसनगर
प्रबंधक, मीराबाई स्मारक, नागौर

कबीरदास जी कहते हैं, ''ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग।'' जैसे चकमक पत्थर में आग छिपी रहती है, तिल में तेल विद्यमान रहता है उसी तरह ईश्वर का वास भी व्यक्ति में ही रहता है, बस उसे खोज निकालने की जरूरत है। तिल के नन्हे से बीज में छिपा तेल भी सर्दी के इन दिनों में ऊर्जा का अमृततुल्य स्रोत है और उसे परम्परागत रूप से खोज निकालने का काम कच्ची घाणियों द्वारा सदियों से किया जा रहा है।

पूरे प्रदेश की तरह मारवाड़ में भी सर्दी के दिनों में ग्रामीणों का खान-पान बदल जाता है। ''बारह कोसां बोली पलटे, वनफल पलटे पाकां'' कहावत के अनुसार प्रत्येक 12 कोस या 36 किमी की दूरी पर खान-पान, रहन-सहन के साथ बोली भी बदल जाती है। क्षेत्र में दीपावली से मकर संक्रांति तक शीतकाल के दिनों में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में तिल व इससे बनने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। खेतों से नया बाजरा आते ही तिल का तेल, गुड़ व खीचड़ा बड़े चाव से खाया जाता है।

तिल का तेल यानी सर्दियों का अमृत

सर्दी शुरू होने के साथ ही सेहत का मेवा कहलाने वाले तिल के तेल की महक फैलने लग जाती है। तिल के तेल को अत्यधिक पौष्टिक माना जाता है। इसी कारण प्रदेश में आमजन सर्दियों में इस तेल का उपयोग बड़े चाव से करते हैं। आयुर्वेद ग्रंथ भावप्रकाश निघन्टू के अनुसार तिल की प्राय: सभी प्रांतों में आदिकाल से खेती की जा रही है। यह शाखायुक्त पौधा 3-4 फीट ऊंचा होता है। इसका पुष्प विभिन्न रंगों सहित नलीकार में होता है। इसकी फली अनेक

बीजों से युक्त होती है। लैटिन भाषा में तिल को ''सिसेमम सीडम'', नायगरम सीडम, सिसेम जिंतिली'' व संस्कृत में ''पितृतर्पण'' व ''हीम धान्य'' कहते हैं। तिल के तेल में मिघ्न गुण की विशेषता होने से प्राचीन काल में मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिये इसका उपयोग किया जाता था। आयुर्वेद में तिल को सर्वश्रेष्ठ औषधि भी बतलाया गया है। तिलों का उपयोग कई प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। इन दिनों बाजार में सफेद, काले व हल्के लाल किस्म के तिल उपलब्ध हैं। इनमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इनके अलावा तिल में मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस सहित कई प्रकार के विटामिन्स व पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। सर्दी के मौसम में तेल या तिल से बने व्यंजनों का सेवन करने से शरीर की कोशिकाओं और मांसपेशियों को फायदा मिलता है। कच्ची घाणी से निकलने वाला तिल के तेल को सर्दियों में खाने से ऊर्जा मिलती है व मालिश करने से ठंड से बचाव भी होता है।

तिल और मिश्री का काढ़ा पीने से कफ आदि विकार से भी बचा जा सकता है। साथ ही यह वात व पित्त को भी संतुलित करता है, जिससे शरीर निरोग रहता है। प्राचीन काल में नहाते समय तिलों के प्रयोग का भी उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है। मारवाड़ में हर मौसम में खान-पान में बदलाव होता है। जैसे-जैसे ठण्डक बढ़ती है वैसे-वैसे रहन-सहन के साथ-साथ खान-पान में परिवर्तन होता है। इन दिनों विशेषकर कच्ची घाणी से तिल का तेल निकालने का दौर चल रहा है। तिल का तेल इस मौसम के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार व मक्के की रोटी (सोगरा) के साथ तिल का तेल व गुड़ खाया जाता है। विशेषकर मकर संक्रान्ति के पर्व पर तिल के लड्डू, रेवड़ियां, तिलपट्टी, गजक, कच्चर, तिलकुटा आदि सामग्री बनाकर महिलाओं द्वारा आपस में बांटने की परम्परा आज भी कायम है। कच्चर या तिलकुटा पौष्टिकता से परिपूर्ण उत्तम शक्तिवर्धक आहार माना जाता है। जिसे तिल, खोपरा, बादाम व गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में मिलीं पारम्परिक घाणियां

बुचकला गांव

डेगाना क्षेत्र

कुचेरा के पास प्राप्त

लाडनू क्षेत्र

मेड़ता

लौहे की घाणी

रूप बदलती कच्ची घाणी

परम्परागत घाणियों में वर्तमान समय तक काफी बदलाव आया है। नागौर जिला क्षेत्र में कई जगह प्राचीन घाणियां मिली हैं जो लाल रंग के मजबूत पत्थरों से बनी हुई हैं। यहां जोजरी व लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में खुदाई में निकली यह घाणियां 8वीं से 13वीं सदी की मानी जाती हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उस काल में यहां तिल की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती थी। मेड़ता की सबसे पुरानी एक मात्र घाणी शहर के मध्य में स्थित है, जहां प्रतिदिन दूर-दराज से तेल निकलवाने वालों की कतारें देखने को मिलती हैं।

सत्तर वर्षीय पुनाराम भाटी बताते हैं कि पुरखों की इस परम्परा को वे आज भी कायम रखे हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे हैं। समय के साथ-साथ इन घाणियों में बदलाव जरूर आ गया है। बीस वर्ष पहले खुले बाड़े में बैल की घाणी हुआ करती थी। वर्तमान समय में तिल के तेल की मांग बढ़ने लगी तो घाणियों का स्वरूप भी बदलने लगा है। उन्होंने अब नए दौर की, बिजली से संचालित होने वाली घाणी को स्थापित किया है। देशी बबूल की मजबूत लकड़ी से बनी घाणी का सारा कार्य लाट करती है। लकड़ी की घाणी में अंग्रेजी के यू आकार के ढांचे में तिल की पिसाई करके तेल निकाला जाता है।

लकड़ी का स्थान अब लोहे के बने खोखे ने तथा बैल का स्थान बिजली की मोटर ने ले लिया है। वहीं कहीं-कहीं देशी जुगाड़ की घाणियां भी देखने को मिलती हैं। जिसमें बैलों की जगह बाइक को जोड़कर यह कार्य और आसान कर दिया गया है। महंगाई के दौर में बैलों को रखना उनके चारे-पानी व आवास पर खर्चा महंगा होता था। इसके अलावा बिजली के कनेक्शन की अपरिहार्यता से भी इस जुगाड़ घाणी ने छुटकारा दिला दिया है। साथ ही इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान हो गया है। मगर पुरानी घाणियों का दृश्य अब दुर्लभ हो गया है।

तेल निकालने का तरीका

घाणी से तेल बनाने का तरीका आसान है। सबसे पहले तिल को साफ करके मशीन या घाणी में डाला जाता है। इसके बाद 500 ग्राम गर्म पानी मिलाया जाता है। लगभग पन्द्रह मिनट बाद तेल निकलना शुरू हो जाता है। इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि लोग खिंचे चले आते हैं।

10 किलोग्राम तिल से एक घाणी निकलती है। जिसमें लगभग चार से पांच किलो तेल निकलता है। एक घाणी निकालने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। औषधीय गुणों से भरपूर इस तेल को ''अमृत रूपी तेल'' की संज्ञा दी जाती है।

शरद महोत्सव-2021 का आगाज

योजनाबद्ध विकास से निखरेगा माउण्ट आबू

माउण्ट आबू राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है। खासकर मानसून के दौरान इसकी हरितिमा देखते ही बनती है। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के इस पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसके योजनाबद्ध विकास के लिए पर्यटन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग दोनों को योजनाबद्ध रूप से काम करना होगा। ताकि इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाया जा सके। इसी मंशा से पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने माउण्ट आबू विकास समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए थे। आबू पर्वत नगर पालिका द्वारा शरद महोत्सव-2021 मनाया जा रहा है। माउण्ट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील पर गांधी वाटिका में गांधीजी की प्रतिमा का अनावरण तथा महात्मा गांधी पुस्तकालय प्रारम्भ किया गया है। झील के किचन गार्डन पर पार्किंग एवं टेरेस गार्डन भी बनाया जाएगा। यहां शरद महोत्सव करीब तीस साल से मनाया जा रहा है।

प्रदेश में पर्यटन और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों को बढ़ावा प्राथमिकता का विषय है। पर्यटन से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए ही प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहित किए जाने का कार्य जारी है। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पहली बार 500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया गया है। इस कोष से पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, उनके संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांडिंग जैसे कार्य होने हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की देश और दुनिया में अनूठी पहचान है। यहां की मनभावन संस्कृति, किलों, महलों, बावड़ियों तथा वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट आदि से जुड़े आकर्षक स्थलों को देखने बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। रोजगार में भी पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया के कई मुल्कों की अर्थव्यवस्था तो इस उद्योग से जुड़ी गतिविधियों पर ही निर्भर करती है। पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राजस्थान को इंडिया टुडे ट्यूरिज्म अवार्ड 2021 में बेस्ट आईकोनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टीवल डेस्टीनेशन अवार्ड और ट्रेवल एण्ड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्डस 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के साथ सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और कोन्डेनास्ट ट्रेवलर अवार्ड-2021 में बेस्ट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप एवं रनरअप बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन अवार्ड मिले हैं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार पर्यटन विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है।

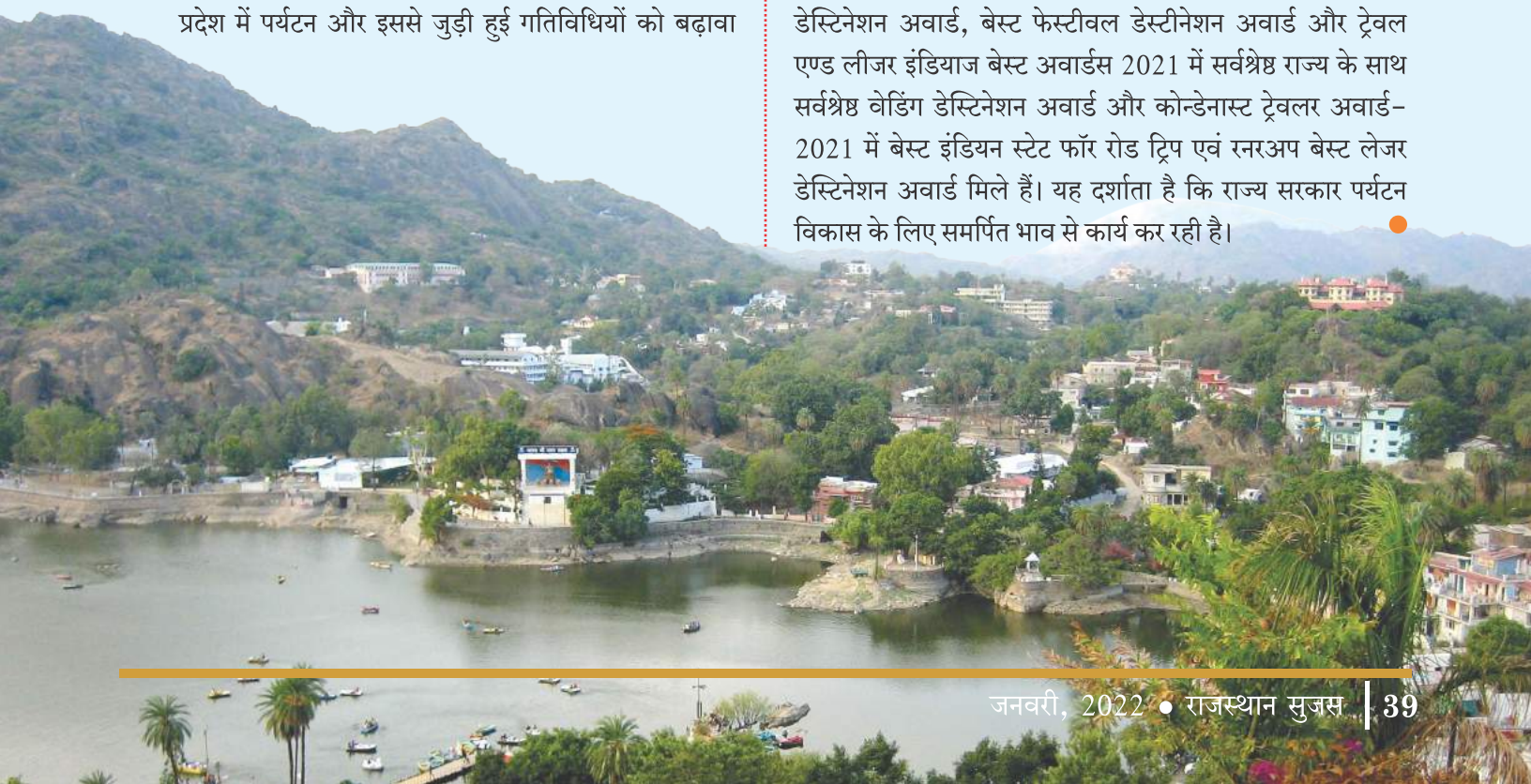

अवशेषों का खजाना : बैराठ–बीजक पहाड़ी

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी वर्तमान विराट नगर (जिला जयपुर) में स्थित बीजक की पहाड़ी पर बौद्धमठ के सुनहरे दिनों के विहार स्तूप, मठ और चैत्य (चैत्यगृह) आदि अवशेष आज भी मौजूद हैं। राजा अशोक महान ने तीसरी सदी ई.पू. अपने शासन काल के दौरान बैराठ की यात्रा की और यहां प्रवास किया। अशोक ने यहां उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से धम्म और विपश्यना की शिक्षा ग्रहण की।

गोल मन्दिर – बीजक पहाड़ी पर स्थित गोल मन्दिर के अवशेष सबसे पुरानी संरचना है, जिसकी बाहरी दीवारों पर बौद्ध शिलालेख बने हुए थे, जो अशोक काल के दौरान ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऊपर वाला प्लेटफार्म, नीचे वाले प्लेटफॉर्म से 30 फीट ऊंचा है जहां राजा अशोक द्वारा उत्कीर्ण दूसरे पत्थर को देख सकते हैं जो विशाल ग्रेनाइट पत्थर है। वर्तमान में बीजक पहाड़ी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित है।

विराटपुर वर्तमान बैराठ या विराटनगर है खुदाई में प्राप्त सामग्री से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह क्षेत्र सिन्धु घाटी के प्रागेतिहासिक काल का समकालीन है। यहां प्रागेतिहासिक काल से लेकर बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्तकाल एवं मुगलकाल तक के अवशेष मिले हैं।

भाब्रु शिलालेख – इसका नामकरण स्थानीय भाब्रु नामक गांव के नाम पर किया गया है। इसे बीजक पहाड़ी से कैप्टन वर्ट ने 1837 ई. में अशोक का पालि भाषा में लिखा प्रसिद्ध भाब्रु शिलालेख खोजा था। इसके अलावा यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मन्दिर और अशोक स्तम्भ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी मौर्यकालीन अवशेष हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रान्ता मिहिरकुल ने बैराठ का विध्वंस कर दिया था।

खंडहरों की खुदाई में मिट्टी की पकाई गई ईंट, यूनानी मुद्राएं पंचमार्का की मुद्राएं, हाथ बुना सूती कपड़ा, मृदभांड, स्वास्तिक और

त्रिरत्न के चिह्न लौह एवं तांबे की कृतियों को बनाने वाले औजार इत्यादि मिले हैं। गोल मन्दिर के उत्खनन में पूजापात्र, थालियां, घड़े, खप्पर, नाचते हुए पक्षी, धूपदान इत्यादि मिले हैं।

महाभारत कालीन अवशेष– महाभारत के दौरान पाण्डवों का अज्ञातवास का स्थान भी विराटनगर रहा, 8 जहां भीम तालाब, भीम लत, भीम गड्ढा, भीम की डूंगरी इत्यादि आज भी मौजूद हैं। बैराठ की पहाड़ियों में मेड़ के समीप स्थानीय बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। बैराठ में ही महाभारतकालीन आराध्यदेव भगवान श्री केशवराम का मन्दिर भी है जिसमें तीन कृष्ण एवं तीन विष्णु की प्रतिमाएं 64 खम्भे एवं 108 टोड़ी हैं।

ईको साउण्ड का रहस्य एवं रोमांच – बीजक पहाड़ी पर स्थित गोल मन्दिर के अवशेषों में एक अजीब रहस्य और रोमांच देखने को मिलता है। मन्दिर संरचना के बीचों-बीच वाले स्थान पर बोलने या कोई आवाज करने पर ईको ध्वनि सुनाई देती है। इतिहास विज्ञों का मानना है कि चैत्यगृह में विपश्यना साधना समाधि के दौरान मंत्रों के

उच्चारण की गूंज इसी ईको साउण्ड के माध्यम से साधकों तक प्रसारित होती होगी। खास बात यह है कि उस गोल स्थान पर बैठकर बोलने पर ईको की गूंज ज्यादा तेज आती है, जैसे माइक लगा हुआ हो। यह अद्भुत विज्ञान प्राचीन भारत की देन है, जो हमें रोमांचित करता है।

विपश्यना – साधना और ध्यान की अति प्राचीन अद्भुत भारतीय विद्या जिसे भगवान बुद्ध ने खोजा और स्वयं अपनाकर सम्यक संबुद्ध बने, अरिहन्त हुए और बोधिसत्व को प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने अनेक भिक्षुओं को विपश्यना सिखाई, जिन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार-प्रसार किया और बोधिसत्व प्राप्त किया। लेकिन कालान्तर में यह विद्या लुप्त प्रायः हो गई, परन्तु म्यांमार (बर्मा या ब्रहम् देश) में यह शुद्ध रूप में जीवित रही।

भारतीय मूल के उद्योगपति पद्म भूषण श्री सत्यनारायण गोयनका (1924-2013) इसे बर्मा में आचार्य समाजी ऊ बासिन (1899-1971) से सीखकर 1969 में भारत लेकर आए। गोयनका जी ने सबसे पहले हैदराबाद, फिर इगतपुरी (महाराष्ट्र) और फिर गलता जी (जयपुर) में विपश्यना साधना केन्द्र स्थापित किए। आज विश्व के करीब 94 देशों में 400 से अधिक विपश्यना साधना केन्द्र संचालित हैं। आधुनिक भारत में विपश्यना के संस्थापक आचार्य गोयनका जी के अनुसार - विपश्यना ध्यान पद्धति चित्त (मनन) की बात वास्तविक सुख-शान्ति और उपयोगी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की एक सख्त, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत कला है।

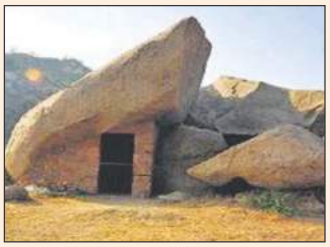

हर घर जल: प्रयास सजग-सतत-सफल

मनमोहन हर्ष
उप निदेशक

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने सजगता के साथ सतत रूप से सफल प्रयास कर आमजन के जीवन में सुखद बदलाव लाने का कार्य किया है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समयबद्ध पेयजल प्रबंधन करते हुए जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर जल' कनेक्शन देने तथा अन्य पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने के लिए कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के कारण उपजी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच जलदाय विभाग की टीम ने पूर्ण मनोयोग के साथ कर्तव्य के हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस कारण मुश्किल हालात में लोगों को पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई।

जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जलदाय विभाग सहित सभी विभागों में जनहित में हुए ऐतिहासिक कार्यों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि आने वाले दिनों में जनता को निर्बाध, नियमित और पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर निरंतर पूरा फोकस रहेगा। पानी के वेस्टेज को रोकने के लिए आमजन के सहयोग से हर स्तर पर सजगता के साथ पुरजोर प्रयास किए जाएंगे। डॉ. जोशी ने अधिकारियों को जेजेएम सहित सभी परियोजनाओं के कार्यों को इस सोच के साथ गति देने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका पूरा फायदा आमजन को मिले।

जल जीवन मिशन: ग्रामीणों के द्वार पर 'हर घर जल' कनेक्शन की दस्तक जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को वर्ष 2024 तक 'हर घर जल' कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अगस्त, 2019 में जेजेएम के लागू होने से पहले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर जल' कनेक्शन की संख्या 11 लाख 74 हजार 131 थी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने जेजेएम की शुरुआत से लेकर अब तक 10 लाख 52 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा और प्रदान कर दी गई है। अब प्रदेश में 22 लाख 25 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस संख्या में प्रतिदिन सैकड़ों 'हर घर जल' कनेक्शन का इजाफा होता जा रहा है।

रिकॉर्ड स्वीकृतियों से बदली तस्वीर

प्रदेश में जल जीवन मिशन में कैलेंडर वर्ष 2021 गांव-ढाणियों के लिए रिकॉर्ड स्तर पर 'हर घर नल कनेक्शन' की स्वीकृतियों के नाम रहा है। जेजेएम में सभी जिलों से प्राप्त होने वाले 'हर घर नल कनेक्शन' के प्रस्तावों को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक औसतन हर माह एसएलएसएससी की बैठक आयोजित करते हुए वृहद पैमाने पर स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन रिकार्ड स्वीकृतियों की बदौलत प्रदेश में जेजेएम के कार्यों में इस प्रकार गति देखने को मिली है कि बदली हुई स्थितियों में विभाग के पास न केवल चालू वित्तीय वर्ष अपितु वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 में कराए जाने वाले कार्यों की भी स्वीकृतियां भी अभी से उपलब्ध हैं। एसएलएसएससी की नियमित बैठकों के बाद वर्तमान में प्रदेश के 36

हजार से अधिक गांवों में 9 हजार 345 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में करीब 87 लाख परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन देने प्रस्तावित है जिन पर करीब 60 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

तकनीकी प्रक्रियाओं के निष्पादन में भी तेजी

जेजेएम में रिकॉर्ड स्वीकृतियां जारी करने के साथ ही प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बीच जलदाय विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों ने वर्चुअल मोड का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए तकनीकी प्रक्रियाओं के निष्पादन की दिशा में भी समन्वित प्रयास किए है।

इसी का परिणाम है कि वर्तमान में जारी 'हर घर जल' कनेक्शन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के साथ साथ ही बड़े पैमाने पर तकनीकी स्वीकृतियां, निविदाएं और कार्यादेश जारी करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है।

अब तक विभाग द्वारा रेग्यूलर विंग और वृहद पेयजल परियोजनाओं में स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 29 लाख 36 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि 25 लाख 32 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन देने का कार्य मौके पर चल रहा है। इसके साथ ही 21 हजार 940 गांवों में 7814 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां (53 लाख 84 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन के लिए) तथा 22 हजार 684 गांवों में 7572 स्कीम्स (54 लाख 81 हजार से अधिक 'हर घर जल' कनेक्शन के लिए) की निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं।

पेयजल गुणवत्ता के कार्यो पर फोकस

राज्य सरकार प्रदेश में जेजेएम तथा अन्य पेयजल परियोजनाओं के तहत लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पर पूरा फोकस कर रही है। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आम नागरिकों के लिए 16 बिंदुओं पर आधारित पेयजल गुणवत्ता परीक्षण की दर 1000 रुपए से घटाकर 600 रुपये कर दी है। जेजेएम के तहत वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस (डब्ल्यूक्यूएमएस) प्रोगाम में वर्ष 2020-21 की वार्षिक योजना में 67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत जयपुर में पानीपेच पर 3 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेट लेबोरेटरी का नया भवन बनाने और चालू वर्ष में प्रदेश की 353 पंचायत समितियों में से 102 पर ब्लॉक पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही अब तक राज्य की 33 में से 32 जिला पेयजल जांच प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 'एनएबीएल एक्रीडिएशन' दिलाने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। इसी प्रकार जयपुर में संचालित राजकीय मोबाइल प्रगति पर है।

जलदाय विभाग के द्वारा वर्तमान में जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के 20 जिलों में आउटसोर्सिंग से मोबाईल प्रयोगशालाओं का संचालन भी किया जा रहा है। जेजेएम में प्रदेश के गांवों में गठित ग्राम जल एव स्वच्छता समिति के सदस्यों को 'फील्ड टेस्टिंग किट' के माध्यम से समय-समय पर पेयजल के नमूनों की जांच के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। विभाग द्वारा 12 हजार 'फील्ड टेस्टिंग किट' की खरीद की गई है। इनका राज्य के सभी 11 हजार 343 ग्राम पंचायतों में वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को अपने वाहन में फील्ड टेस्टिंग किट रखने तथा अपनी सभी फील्ड विजिट में इसका उपयोग करते हुए लोगों की मौजूदगी में पेयजल गुणवत्ता की जांच के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

श्रेष्ठता को प्रोत्साहन के लिए पहल

जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभाग की टीम कड़ी मेहनत में जुटी है। इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं उनके कार्य मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की पहल पर 'परफॉर्मेंस ऑडिट मैकेनिज्म' तैयार किया गया है। इस मैकेनिज्म के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर चार श्रेणियों में अधिकारियों को स्टेट लेवल अवार्ड दिया जाएगा। जलदाय विभाग हर साल राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगा, इसमें प्रति वर्ष 2 सम्भागीय आयुक्त, 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 5 जिला कलक्टर एवं 5 अधीक्षण अभियंताओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर भी इसी तर्ज पर अधिकारियों-कार्मिकों को प्रोत्साहन के लिए योजना बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पहली बार क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल लागू

प्रदेश में जल जीवन मिशन सहित अन्य पेयजल परियोजनाओं के सभी कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग द्वारा पहली बार क्वालिटी एश्योरेंस एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल तैयार कर इसे लागू किया गया है। इस मैनुअल में सभी कार्यो में निर्धारित नॉर्म्स की पालना तथा पारदर्शिता के लिए सभी स्तरों पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देशों का समावेश किया गया है।

इसमें गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अभियन्ताओं व योजनाओं के क्रियान्वयन से सीधे तौर पर जुड़े अभियन्ताओं की भूमिका तय करते हुए निर्माण सामग्री के नॉर्म्स के अनुरूप नहीं होने पर संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

जयपुर शहर को बीसलपुर से पेयजल की सौगात

पीएचईडी के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल कार्यों पर 1274.14

जयपुर शहर को बीसलपुर से पेयजल की सौगात

पीएचईडी के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल कार्यों पर 1274.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। जयपुर शहर की नागरिकों की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बीसलपुर परियोजना स्टेज-2 फेज-प्रथम के लिए 288.90 करोड़ रुपए की स्वीकृत प्रदान की। इससे जयपुर शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 170 एमएलडी अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध होगा। पृथ्वीराज नगर के लिए राज्य सरकार द्वारा बीसलपुर बांध से 170 एमएलडी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए 563.93 करोड़ रुपये की बीसलपुर-पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम स्टेज-प्रथम पेयजल परियोजना स्वीकृत की गई। इस योजना से 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बुनियादी ढांचा विकसित कर पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के लोगों के लिए 295.51 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इन दोनों योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है, जिसे अक्टूबर 2022 तक पूरे किए जाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस को भी बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए 15.60 करोड़ रुपये की परियोजना आरम्भ की गई। इसका भी कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

वृहद पेयजल परियोजनाओं गांव व ढाणियां और शहर लाभांवित

वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोत से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों को आंशिक, 4065 ग्राम एवं 3990 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। इस दौरान 14 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को पूरा करते हुए विभिन्न जिलों में लोगों को लाभान्वित किया गया है।

इनमें इन्द्रगढ़-चाकन पेयजल परियोजना-जिला बूंदी, चम्बल-बूंदी कलस्टर परियोजना (विस्तार चम्बल-भीलवाडा परियोजना), बोरावास-पदमपुरा पेयजल परियोजना-जिला कोटा, अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, प्रतापगढ़ शहर की विधमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन कार्य, जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना (खो-नागोरियन), बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ की 344 ग्रामों की पेयजल परियोजना, राजगढ़ पेयजल परियोजना-जिला झालावाड़, फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना-जिला सीकर, पांचला घेवरा चिराई क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना-जिला जोधपुर, उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी पेयजल परियोजना-जिला बाड़मेर, शायगढ़ पेयजल परियोजना-जिला बारां, गागरीन पेयजल परियोजना- जिला झालावाड़ एवं नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण के कार्यो पूरा कर सम्बंधित क्षेत्रों के निवासियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं

जलदाय विभाग द्वारा जोधपुर, बाड़मेर एवं पाली जिले के 6 शहर तथा 2167 गांवों के लिए 1799 करोड़ रुपये की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना -तृतीय चरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो नीति निर्धारण समिति से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है। इसके साथ नागौर जिले के तीन शहरी क्षेत्रों मेड़ता शहर, डेगाना एवं लाडनूं में पेयजल वितरण तंत्र के पुनर्गठन के लिए भी विभाग द्वारा 45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। मेड़ता शहर के लिए 18.73 करोड़ रुपये, डेगाना के लिए 11.86 करोड़ रुपये एवं लाडनूं के लिए 14.41 करोड़ रुपये की योजना प्रारम्भ की गई, जिसका कार्य प्रगति पर है। मेड़ता शहर एवं डेगाना का कार्य अगस्त 2022 एवं लाडनूं का कार्य फरवरी 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ऑनलाइन पेयजल कनेक्शन की सौगात

प्रदेश में उपभोक्ताओं को ऑनलाईन पेयजल कनेक्शन के लिए अक्टूबर 2020 में जलदाय विभाग द्वारा 'अनलाईन एप' लॉन्च किया गया। इससे चरणबद्ध रूप से राज्य में उपभोक्ताओं को सुगमता से घर बैठे पानी के कनेक्शन की सुविधा मिलेगी और अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर निकालने से निजात मिलेगी। 'आनलाइन ऐप' से आवेदन सुविधा पहले चरण में जयपुर के जगतपुरा और विद्याधरनगर के क्षेत्र के निवासियों के लिए आरम्भ की गई थी, अब यह सुविधा जयपुर शहर में उपलब्ध है। विभाग द्वारा आने वाले दिनों में इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। आनलाइन एप तैयार कर विभाग द्वारा जन घोषणा पत्र में डोर स्टेप डिलीवरी के तहत की गई घोषणा क्रियान्विति की गई है। इसके अलावा विभाग द्वारा मैटेरियल मैनेजमेन्ट का ऑनलाइन प्रबंधन, ऑनलाईन भण्डार मॉड्यूल तथा पानी के बिलों के ऑनलाईन भुगतान की सेवा भी प्रारम्भ की गई है।

विशेष कार्य, उपलब्धियां और नवाचार

जलदाय विभाग द्वारा गुणवता प्रभावित बस्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इनमें 1158 आरओ प्लांट लगाकर चालू किए गए हैं। इसके साथ ही फ्लोराइड से प्रभावित गांव एवं ढाणियों में 1953 सौर उर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट (डीएफयू) भी स्थापित किए गए हैं। इन बस्तियों में निवासरत लोगों के लिए 7591 नये नलकूप एवं 15 हजार 387 नये हैण्डपम्प लगाकर चालू किए गए हैं, जबकि 7 लाख 29 हजार से अधिक खराब पाए गए हैण्डपम्पों को सुधार कर पुन: चालू किया गया है। अन्य विशेष कार्यो, उपलब्धियों और नवाचारों का जिक्र किया जाए तो राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घरेलू जल सम्बन्ध महिला मुखिया के नाम से ही जारी किए जाने को वरीयता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस दौरान 811 अनुसूचित जाति एवं 1051 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य हेबीटेशन को पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य भी किया गया है।

21 छात्रावास भवन निर्माण, 8 आवासीय विद्यालय मंजूर

तालीम और स्वरोजगार से जुड़ रहा अल्पसंख्यक वर्ग

राज्य सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण और उनमें उचित सुविधाएं विकसित कर रही है ताकि यहां पढ़ रहे बच्चों को हर विषय की अच्छी तालीम मिले। मदरसा बोर्ड का एक्ट भी बनाया गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है। इस वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा शिक्षा के लिए रियायती ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल पर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2013-2014 तक के मंजूर सभी बकाया ऋणों की माफी के लिए अल्पसंख्यक आम ऋण माफी (एमनेस्टी) योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना के पहले चरण में 5149 लोगों को 40.33 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। आरएएस-2021 भर्ती में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 17 तथा कार्यक्रम अधिकारी के 33 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इससे विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जैसी योजनाओं से अन्य वर्गों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी भरपूर लाभ मिल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 8 आवासीय विद्यालय मंजूर किए हैं। साथ ही उन्हें बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 21 छात्रावास भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है। अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के विकास कोष का गठन किया जा रहा है। इससे अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। हर वर्ग को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। सभी परिवारों को इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए।

सहकारिता : किसान कल्याण के 7 स्तम्भ

देश के करीब दो-तिहाई जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियां हैं और अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। देश-प्रदेश के विकास के लिए किसानों की खुशहाली बेहद जरूरी है और इसके लिए सहकारिता एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इसी सोच का आधार मानते हुए प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में नीतिगत बदलाव के साथ ही नवाचारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री गहलोत किसानों के सशक्तीकरण के लिए सहकारिता को कृषि साख, वित्तीय समावेशन, कृषि आदान, सामाजिक सुरक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सहकारी समितियों को स्वावलम्बी बनाने जैसे सात मुख्य आधार स्तम्भों से जोड़कर कार्य कर रहे हैं। साथ ही उनके समावेशी विकास की दिशा में कई कार्य कर रहे हैं।

इनमें राज सहकार पोर्टल से पारदर्शिता को बढ़ावा देना, एकीकृत किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्रों की शुरुआत, यूरिया एवं डीएपी का बफर स्टॉक, बायोमैट्रिक प्रणाली से समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन खरीद, ऑनलाइन वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन, कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना, सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण, पैक्स एवं लेम्पस को मल्टी सर्विस सेन्टर बनाना जैसी योजनाएं एवं निर्णय लागू कर अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रों में बढ़ोतरी, किसानों से सीधी खरीद के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडियों का दर्जा देना, खाद एवं बीज के अग्रिम भंडारण के विषय में राज्य सरकार द्वारा किसान हितैषी निर्णय किए गए हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं:-

ओटाराम चौधरी
सहायक निदेशक

राज सहकार पोर्टल से संस्थाओं में पारदर्शिता की शुरुआत

राज्य सरकार के उत्तरदायित्व एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत राज सहकार पोर्टल बनाया गया है। यह एक एकीकृत प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म के द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारी, सहकारी संस्थाएं एवं आम नागरिक विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं यथा अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान, नई सहकारी संस्थाओं के पंजीयन, क्लबों/एन.जी.ओ./नागरिक संस्थाओं का पंजीयन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की खेल समितियों के पंजीयन एवं इससे संबंधित समस्त कार्य को ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई है।

किसान को उपज का वाजिब दाम दिलाने की ठोस शुरुआत

प्रदेश में रबी एवं खरीफ सीजन की उपजों को बायोमैट्रिक (आधार आधारित) सत्यापन से ऑनलाइन पंजीयन कर किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय किया गया। यह सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लेकर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खरीद केन्द्रों की स्थापना कर प्रदेश में मूंग, उड़द, सोयबीन, मूंगफली, गेहूं, सरसों एवं चना के समर्थन मूल्य पर 29.52 लाख मीट्रिक टन की उपज खरीदी गई। जिसका मूल्य 12 हजार 805 करोड़ रुपये है। रिकॉर्ड खरीदारी कर लाखों किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया।

उपज बेचान के 4 दिन में किसान को भुगतान

प्रदेश में किसानों से होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीद में त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वेयर हाउस ई-रिसिप्ट जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। सरकार

के इस कदम से खरीद केन्द्र से वेयर हाउस भेजे जाने वाली उपज त्वरित ढंग से जमा होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार से भुगतान भी शीघ्र प्राप्त होने लगा है। किसानों को 4 दिवस में ही उपज का भुगतान उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा रहा है।

गोदाम निर्माण से भंडारण क्षमता में 89200 मीट्रिक टन की वृद्धि

ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उनकी मांग के अनुसार कृषि आदान यथा-खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की उपज के भंडारण के लिए गोदामों का होना आवश्यक है। प्रदेश में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों सहित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदामों के निर्माण को सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा में वृद्धि करने के लिए रिकॉर्ड 807 (767 जीएसएस व 40 केवीएसएस) गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इससे राज्य की भंडारण क्षमता में 89200 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई-मित्र केन्द्रों की सुविधा से जोड़ा

राज्य सरकार की ओर से ई-मित्र केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही 400 से अधिक सेवायें उपलब्ध हो सकें, इसके लिए महात्मा गांधी के 150वें जयन्ती वर्ष 2 अक्टूबर, 2019 से अभियान चलाकर सभी 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ई-मित्र केन्द्रों की सुविधा से जोड़ने की शुरुआत की गई है। जिसका नतीजा है कि लगभग 5 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्रों की सुविधा आम लोगों को मिलने लगी है।

किसान सेवा पोर्टल से सुविधा

अन्नदाता को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। यह पोर्टल सरकार के नीति निर्धारण में सहायक होगा, वहीं एक ही छत के नीचे किसानों को सभी प्रकार की सेवायें भी प्रदान कर रहा है। डिजिटल, वित्त और सामाजिक समावेश में यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

सीधी खरीद के लिए गौण मंडियों में की वृद्धि

किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा खरीद की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने किसानों से सीधी खरीद करने के लिए 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मण्डी के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे किसानों को अपने खेत एवं गांव के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा के साथ-साथ कृषि उपज मंडियों के अनुरूप ही कृषि जिन्सों को खुली नीलामी में बेचकर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य की सुविधा मिल रही है। इससे 31 हजार 877 किसानों को लाभ मिला है तथा उनकी 7 लाख 64 हजार 737 क्विंटल उपज (16 फसल) की खरीद हुई है। जिसकी राशि 200.45 करोड़ रुपये है।

''प्रदेश के अन्नदाता किसान का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कृषि कार्यों से आय की अनवरतता के लिये मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इन निर्णयों का सकारात्मक असर प्रदेश के किसानों के जीवन पर नजर आने लगा है।'' श्री उदयलाल आंजना, सहकारिता मंत्री

पैक्स एवं लैम्पस से मल्टी सर्विस सेन्टर की सुविधा

किसानों को खाद, बीज, ऋण सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेन्टर (गोदाम, धर्मकांटा, शीतलन गृह, प्रोसेसिंग यूनिट, सुपर मार्केट सहित अन्य सुविधाएं) के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। बहुउद्देश्य सेवा केन्द्रों के रूप में 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को चिह्नित किया जा चुका है। जिनमें से नाबार्ड को प्रेषित 324 पैक्स/लैम्पस के प्रस्ताव में से 51.03 करोड़ रुपये के 280 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। एग्री इन्फ्रा फंड योजना के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा विभिन्न जीएसएस में 115 प्रोजेक्ट में से 92 प्रोजेक्ट के लिए 11.43 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।

424 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू

फसल चक्रों में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकाधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग सेन्टर्स से जोड़ा जा रहा है, 139 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हो चुकी है। 11.12 करोड़ रुपये का अनुदान ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया गया है। इन समितियों पर किसानों को वाजिब किराए पर ट्रैक्टर, हल, रोटावेटर, थ्रेसर, ट्रॉली सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 285 जीएसएस एवं केवीएसएस में कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

774 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

सहकारिता से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य की ओर कदम उठाए गए हैं। जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता के ढांचे का विस्तार होगा तथा नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन से किसानों को उनकी ग्राम पंचायत में ही ऋण सुविधा, खाद-बीज, ई-मित्र जैसी अन्य सुविधाएं मिलेंगी। विभिन्न जिलों में 774 पैक्स/लैम्पस के गठन को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन समितियों के गठन से 2 लाख से अधिक लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ा जा चुका है। किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार ने कोविड-19 जैसी आपदा में भी दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेकर किसानों को राहत पहुंचाई है।

'प्रशासन गांवों के संग' अभियान

बेजुबां जानवरों को भी मिली राहत

शिविरों के दौरान हुआ पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार
दुर्गम पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले पशुपालकों तक पहुंचाई पशु चिकित्सा सेवा

सोहनलाल
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी

राज्य सरकार की ओर से आमजन के मौके पर ही काम कर राहत देने के लिए चलाए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान से बेजुबां जानवरों को भी फायदा मिला। शिविरों के दौरान पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं उपचार किया गया। पशुपालन विभाग के काउंटर्स पर दवाइयां व पशुओं से संबंधित बीमारियों की आवश्यक रोकथाम के उद्देश्य से विचार-विमर्श के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। साथ ही विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों ने दूरदराज के दुर्गम पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंचकर पशुपालकों को सेवाएं मुहैया करवाई।

सीकर जिले की पाटन पंचायत समिति के श्यामपुरा गांव में लगे शिविर में 240 पशुओं का टीकाकरण, 485 डोजिंग, 88 डस्टिंग, 10 बधियाकरण, 63 पशुओं की चिकित्सा, 6 पशुओं का गर्भ परीक्षण एवं बांझपन उपचार किया गया, साथ ही 15 पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के आवेदन तैयार कराए गए। यहां लाभान्वित होने वालों में शामिल प्रगतिशील पशुपालक श्री बुधराम वर्मा के लिए यह शिविर बहुत ही राहतकारी साबित हुआ। उनकी दो सौ भेड़-बकरियों के कैम्प स्थल पर ही फड़किया रोधी टीके लग गए और सभी पशुओं को अंत परजीवी एवं कृमिनाशक दवा पिलाई गई है। मौके पर ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का नया आवेदन पत्र भरकर बैंक में जमा करवा दिया। पिछले सालों में मरी भेड़-बकरियों का क्लेम भी मिल गया। इसी प्रकार पिपराली पंचायत समिति के दौलतपुरा गांव में शिविर के दौरान भंवरलाल ख्यालिया की 100 भेड़-बकरियों एवं 10-10 गाय-भैंसों को अंतः कृमिनाशक दवा पिलाई और पीवीआर वेक्सीनेशन किया गया। साथ ही 20 बकरों का बधियाकरण किया गया और केसीसी का आवेदन पत्र तैयार करवा दिया।

डूंगरपुर जिले में पशुपालन विभाग की टीमों ने दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार किया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक कल्पना हिरवाड़े के मुताबिक, इन शिविरों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के पशुपालकों के जानवरों को बेहतर इलाज मुहैया कराया गया। बड़गामा के बापूलाल कटारा, चम्पालाल बामणिया एवं हरिशंकर अहारी तथा तलैया के वीरजी ननोमा, राजू गमेती, करमचंद गमेती एवं खातरा डामोर जैसे हजारों आदिवासी पशुपालकों के भैंस, बकरी, गाय एवं ऊंटों के टीके लगाए गए और उपचार किया गया। विभागीय टीमों ने चीखली पंचायत समिति के बड़गामा, झौंथरी के मांडेला ऊपली एवं खरखुनिया, सीमलवाड़ा के सरथूना एवं डूंका, सागवाड़ा के सुखापादर एवं किशनपुरा तथा बिच्छीवाड़ा पंचायत समिति के मोदर एवं तलैया जैसे दूरस्थ गांवों तक अपनी सेवाएं दी हैं।

जैसलमेर में ऊंटों के सहारे पहुंच किया वैक्सीनेशन और उपचार

जैसलमेर में ऊंटों के सहारे पहुंच कर वैक्सीनेशन और इलाज का कार्य किया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सक वासुदेव गर्ग बताते हैं कि मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में पशुपालकों की आजीविका का प्रमुख साधन पशुधन एवं पशुपालन होने के कारण उनका शिविरों के प्रति खास रुझान दिखाई दिया। पशुपालकों ने विशेष रुचि लेकर दवाइयां प्राप्त की। गोष्ठी का आयोजन कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी एवं विषम परिस्थितियों में पशुपालकों के घर जाकर टीकाकरण, डॉजिंग, डस्टिंग व उपचार का कार्य किया गया। दूरदराज के इलाकों में ऊंटों के सहारे पहुंचकर पशुओं का वैक्सीनेशन और इलाज किया गया।

27 लाख पशुओं का उपचार, 36 लाख का टीकाकरण

अभियान के दौरान विभाग की ओर से राज्यभर में अब तक 10790 शिविरों में 27.03 लाख पशुओं का आवश्यक उपचार, 36 लाख 30 हजार पशुओं का टीकाकरण, 36 लाख 88 हजार पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलायी गई है। 28 लाख 63 हजार पशुओं पर कृमिनाशक दवा का छिड़काव, बांझपन से ग्रसित 1 लाख 35 हजार पशुओं के उपचार के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण एवं पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन पत्र तैयार करवाए गए हैं। गोष्ठियों में 11.16 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

405 पशुपालक सम्मानित

पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाले प्रदेशभर के 405 प्रगतिशील पशुपालकों को पिछले दिनों राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया और शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक ने राज्य स्तर पर बीकानेर जिले के पशुपालक सुरेन्द्र कुमार एवं सीकर जिले के सुभाष चन्द को प्रशस्ति पत्र तथा 50-50 हजार रुपए की राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान कर सम्मानित किया। जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त एवं कलक्टर ने पशुपालकों को सम्मानित किया। जिला स्तर पर सम्मानित होने वाली सात महिला पशुपालकों सहित 68 पशुपालकों को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए तथा पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित होने वाली 32 महिला पशुपालकों सहित 335 पशुपालकों को दस-दस हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गयी है। इस प्रकार प्रदेश के 405 पशुपालकों को 51.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

'सिर साटै, रूंख रहे, तो ई सस्तो जांण'

जैव-विविधता संरक्षण में विश्नोई समाज का योगदान

बद्रीनारायण विश्नोई
तहसीलदार, बाड़मेर

आज से लगभग 600 साल पूर्व जब राजस्थान में राजनीतिक और धार्मिक अस्थिरता का वातावरण था, जनता मुग़लों और अन्य विदेशी आक्रांताओं के शोषण से त्रस्त और दु:खी थी, ऐसे समय में तत्कालीन समाज को सही दिशा देने और उनके प्रबोधन के लिए संत जाम्भोजी का जन्म सन् 1451 में राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से लगभग 55 कि.मी. दूर उत्तर दिशा स्थित राजस्व ग्राम पीपासर में हुआ था। उनकी माता का नाम हांसा (हंसा) और पिता का लोहट था।

संत जाम्भोजी ने मानव जीवन और उनके आचरण से जुड़े 29 नियम बतला कर, सन् 1485 (संवत् 1542) में 'विष्णोई (विश्नोई) संप्रदाय' की स्थापना की। संत जाम्भोजी की सबद वाणियों से प्रेरित होकर 'विष्णोई (विश्नोई) संप्रदाय' ने इन 29 नियमों को अपनाया। उनके बतलाए नियम जीव-जंतुओं के प्रति दया, पालन-पोषण और पर्यावरण-संरक्षण ('जीव-दया पालणी, रूंख लीलौ नहं घावै।') के प्रति विश्नोई सम्प्रदाय की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। इन नियमों का आज जैव-विविधता और पर्यावरण संरक्षण में विशेष महत्व है।

संत जाम्भोजी की सबद वाणियों और विचारों को बड़ी गहनता से अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इन 29 नियमों में संसार की हर समस्या का समाधान निहित है। संत जाम्भोजी ने मानव जीवन, जीव-जंतु और प्र.ति से जुड़े हर विषय पर अपनी पवित्र वाणी द्वारा विश्व-समुदाय को सचेत और जाग्रत करने का अनुकरणीय कार्य किया है। उन्होंने आज से लगभग 570 वर्ष पूर्व विश्नोई सम्प्रदाय सहित सम्पूर्ण विश्व को बतलाया कि जीवों का पालन-पोषण किया जाए और हरे वृक्ष नहीं काटे जाएं।

संत जाम्भोजी की वाणियों और विचारों को आत्म-सात् करते हुए आज से लगभग 291 वर्ष पूर्व जोधपुर जिला स्थित खेजड़ली

स्मारक

गांव में खेजड़ी-वृक्षों की रक्षार्थ विश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने अमृता विश्नोई के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष से चिपक कर, प्राणोत्सर्ग कर दिया। इस संबंध में उपलब्ध प्रमाण बतलाते हैं कि जोधपुर प्रान्त के तत्कालीन महाराजा अभयसिंह ने किले के निर्माण के लिए चूना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियां कटवा कर लाने का आदेश अपने मंत्री को दिया। इस पर राजा के मंत्री सहित सैनिकों ने जोधपुर जिले के निकटवर्ती गांव खेजड़ली पहुंचकर, निर्ममता और निर्दयतापूर्वक पेड़ों की कटाई प्रारंभ कर दी और राजा के मंत्री ने अपने सैनिकों को बड़े खेजड़ी के पेड़ काटने का आदेश दिया।

तब बहादुर अमृता विश्नोई ने संत जाम्भोजी द्वारा विश्नोई संप्रदाय को बतलाए गए नियमों और खेजड़ी वृक्ष के धार्मिक महत्त्व का हवाला देते हुए खेजड़ी के वृक्ष नहीं कटवाए जाने का आग्रह राजा के मंत्री से किया। लेकिन अमृता विश्नोई द्वारा बार-बार किए गए आग्रह को राजा के मंत्री ने अनदेखा करते हुए खेजड़ी के वृक्ष कटवाए जाने का निश्चय कर लिया, तो बहादुर अमृता विश्नोई खेजड़ी पेड़ से चिपक कर राजा के मंत्री और सैनिकों को पहले उनके सिर को काटे जाने और फिर खेजड़ी वृक्ष को कटवाने को कहा। राजा के मंत्री ने अमृता विश्नोई को बहुत समझाया, लेकिन बहादुर अमृता विश्नोई ने राजा के मंत्री से कहा कि- 'सिर साटै, रूंख रहे, तो ई सस्तो जांण' (मतलब है कि सिर कट जाए और वृक्ष बच जाए, तो भी समझो कि यह सस्ता है)। अमृता विश्नोई खेजड़ी वृक्ष से लगातार चिपकी रही। यह दृश्य देखकर अमृता की तीनों पुत्रियां भी वहां पर पहुंच गईं और वे भी अमृता विश्नोई की भांति खेजड़ी से चिपक गईं। निर्दयी सैनिकों ने अमृता विश्नोई, उनकी तीनों पुत्रियां सहित 363 लोगों के सिर खेजड़ी के वृक्षों के लिए काट डाले। इस प्रकार खेजड़ी वृक्षों के रक्षार्थ, उनसे चिपक कर 363 विश्नोई शहीद हो गए। विश्व इतिहास का कदाचित् यह प्रथम 'चिपको आंदोलन' रहा होगा। पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति विश्नोई समाज की संवेदनशीलता उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है।

'कोविड-19' महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियां दर्शाती हैं कि अब हमें पर्यावरण-संरक्षण के प्रति हमारी सोच, रवैये और नज़रिये को बहुत ही संवेदनशील और सकारात्मक करने की ज़रूरत है। आधुनिकीकरण के नाम पर विकास के अंधी दौड़ ने मानव-प्रकृति के मध्य दूरियां पैदा कर दी हैं।

आज हमें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हमारी सामाजिक चेतना और समझ को व्यापक करते हुए, मानव-प्रकृति के भावनात्मक सम्बन्धों के ताने-बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे मानव-प्रकृति के और क़रीब आएगा। वर्तमान में मानव जाति व जीव-जन्तु के अस्तित्त्व की रक्षा तथा पर्यावरणीय असन्तुलन से जनित खतरों से उन्हें बचाने के लिए विज्ञान और तकनीक का विवेकपूर्वक इस्तेमाल करने की दरक़ार है। आज बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को समझने तथा पर्यावरणीय नीतियों पर अमल करने के लिए पर्यावरण से जुड़ें बेहतर सामाजिक शिक्षण, संस्कृति, चेतना तथा विमर्श की सभी समाजों में आवश्यकता है।

इसलिए अब हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी और दृढ़ राजनीतिक इच्छा-शक्ति से पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करते हुए, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखना होगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय पैनल (आई.पी.सी.सी.) की ओर से जारी छठी जायजा रिपोर्ट (ए.आर.-6, 2021) पर गौर किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से आग़ाह करते हुए, मानव-जाति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह बात सही है कि आज हमने जिस अविवेकपूर्ण तरीक़े से प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन किया है, अगर अब भी हम पर्यावरण संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं बने, तो भावी पीढ़ियां जब पर्यावरणीय असंतुलन से उत्पन्न विनाशकारी प्रभावों का सामना करेगी, तब वे हमें इसके लिए उत्तरदायी मानेगी और शायद ही हमें माफ़ करेगी। ऐसे में जैव विविधता और पर्यावरण-संरक्षण से जुड़ी विश्नोई समाज की समझ और चेतना ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है।

पन्नालाल मेघवाल
संयुक्त निदेशक (से.नि.)

सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षक, समाज सुधारक, शिक्षाविद् एवं कवयित्री थीं। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत में महिलाओं को शिक्षित करने एवं महिला अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की एक महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में जाना जाता है।

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम खन्दोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका विवाह सन् 1840 में केवल नौ वर्ष की उम्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले (ज्योतिबा फुले) से हुआ। जिस समय सावित्रीबाई का विवाह हुआ था, उस समय उनकी स्कूली शिक्षा भी नहीं हुई थी। विवाह के बाद उनके पति ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाते थे।

सन् 1849 में जब ज्योतिबा फुले के पिताजी को यह मालूम हुआ कि ज्योतिबा फुले उसकी पत्नी को घर में पढ़ाते हैं तो उन्होंने रूढ़िवादिता और समाज के डर से ज्योतिबा फुले दंपती को घर से निकाल दिया। इसके बावजूद ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना जारी रखा। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने उनका एडमिशन एक प्रशिक्षण विद्यालय में कराया। सावित्रीबाई फुले ने समाज के विरोध का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की।

अपने पति से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए जबरदस्त कार्य किया। सावित्रीबाई फुले भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की प्रथम महिला शिक्षक बनी। उन्होंने अछूत बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने नवजात कन्या शिशुओं की हत्याओं को रोकने का अभियान चलाया। नवजात कन्याओं शिशुओं के लिए आश्रम खोले। उन्होंने बालिका शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया। सावित्रीबाई फुले लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए समाज की परवाह किए बगैर अनवरत संघर्ष में लगी रहीं। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पुरुषों की तरह सामान अधिकार दिलाने की मुहिम चलाई और उसमें सफलता हासिल की।

सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ समाज की कुरीतियों को समाप्त किया, बल्कि देश की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 19वीं शताब्दी में महिला अधिकारों, बालिका शिक्षा, छुआछूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह तथा विधवा-विवाह जैसी कुरीतियों और समाज में फैले अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया।

सावित्रीबाई फुले देश की महानायिका हैं। उन्हें बालिका शिक्षा के अभियान में सामाजिक विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ा। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिये काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में साथ लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंच कर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले पांच विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला शिक्षक के लिए सन् 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। बालिका शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी के दौर में बालिकाओं को शिक्षित करने की उनके सामने जबरदस्त चुनौती थी। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले न सिर्फ स्वयं शिक्षित हुई, बल्कि अनेक बालिकाओं को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

सावित्रीबाई फुले एक लेखिका एवं कवयित्री भी थीं। उन्होंने सन् 1854 में काव्या फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किया। सन् 1892 में गो गेट एजुकेशन कविता लिखी जिसमें उन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो शिक्षा प्राप्त करके खुद को मुक्त करना चाहते थे। अपने अनुभव और काम के परिणामस्वरूप, वह एक उत्साही नारीवादी बन गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सतत संघर्ष किया। समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं को आगे बढ़ाने के साथ सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की प्रथम महिला शिक्षिका – सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा प्रसार, सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, प्रसूति एवं बाल संरक्षण गृहों की स्थापना, प्लेग महामारी में पीड़ितों की सेवा आदि कार्यों में अद्वितीय योगदान रहा है। सन् 1897 में प्लेग महामारी फैली थी।

सावित्रीबाई प्लेग महामारी में प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। प्लेग रोग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा में लगे रहने के कारण उन्हें भी प्लेग रोग हो गया और 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की उम्र में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई।

महात्मा गांधी नरेगा योजना

जल संरक्षण कार्यों से भूजल स्तर में बढ़ोतरी

जल भराव संरचनाओं से होगा सबको फायदा

सम्पत राम चांदोलिया
सहायक निदेशक

राजस्थान में भिन्न-भिन्न भौगोलिक स्थितियां होने पर प्रदेश विभिन्नताओं में एकता लिए हुए है। राज्य में आषाढ़ माह में आसमान से बरसने वाले अमृत को सहेजने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं में एनिकट, तालाब खुदाई, चेक डैम,जोहड़, टांका, नाडी, फार्म पॉण्ड, परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, स्ट्रगर ट्रेंच, एमपीटी निर्माण आदि निर्माण कार्यो को प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं जिसका लाभ हमेशा मिलता रहेगा। निर्माण कार्यो के माध्यम से ग्रामवासियों को अपने ही गांव में रोजगार मिल रहा है। राज्य की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जा रहे है।

डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में कई स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन हुआ है, जिससे जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए अनेक संरचनाएं निर्मित की जा रही है। नरेगा के तहत चल रहे कार्यो पर स्थानीय गरीब परिवारों को ना केवल रोजगार मिला अपितु स्थायी निर्माण से आने वाले समय में कई प्रकार के लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुए है। ऐसा ही एक उदाहरण जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में आसियावाव ग्राम पंचायत में कच्चे पक्के चेकडेम निर्माण से पानी रूकने से ग्रामीणों को दोहरा फायदा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने से बरसात का पानी बह कर निकल जाता था। चैकडैम के निर्माण से रुका हुआ पानी आस-पास के निचले क्षेत्र में भू-जल स्तर बढ़ा कर खेतों में नमी दे रहा है साथ ही कुओं एवं हैडपम्पों, जलकूपों का भी जल स्तर बढ़ा है।

ऊंचे-ऊंचे पहाड़ो व पथरीली भूमि पर कार्य करना सामग्री पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या थी। पहाड़ों से बह कर निकलने वाले पानी का ठहराव करना है। ग्रामीणों ने विचार-विमर्श कर जगह चिन्हित कर ग्राम पंचायत में चेकडैम निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी नरेगा योजना से कार्य शुरू किया गया। ग्राम पंचायत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य भागों में कच्चे पक्के चेकडेम निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये गये और कार्य प्रारम्भ किये ।

ग्रामीणों ने बताया कि हमारे सामने सबसे बडी समस्या थी पानी का ठहराव कैसे किया जावे, राज्य सरकार ने जल संरक्षण के निर्माण कार्यो को बढ़ावा दिया जिसके फलस्वरूप बारिश होने से चेकडेम पानी से भर कर ऑवर फ्लो होकर बहने लगा। चेकडेम में पहली बरसात में ही पानी ठहरने से निकट समय में ग्रामीणों को पानी की समस्याओं का समाधान हुआ।

कार्य और जीवन की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीणों ने भी दिल खोलकर जलसंरक्षण के कार्य को पूरा किया, आज पानी ठहरने से भूजल स्तर में बढ़ोतरी के साथ ही पानी की उपयोगिता भी समझमें आने लगी है तथा जानवरों, पशु-पक्षियों का भी पीने का पानी मिलने लगा है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले की ग्राम आसियावाव में सामग्री एवं श्रम मद से 13.98 लाख रूपये की लागत से शमशान घाट धर्मा ओदी के पास चेकडेम निर्माण कार्य तैयार करवाया गया इसके निर्माण से पानी रुकने का लाभ तो मिलेगा ही साथ में आस-पास के क्षेत्र भी हरित रहेगा। यह कार्य जून 2020 में शुरू किया गया और जनवरी, 2021 में पूर्ण करवाया गया। चेकडेम निर्माण कार्य पर आस-पास के 4776 मानव दिवस सृजित हुए हैं।

भौगोलिक, धार्मिक, प्राकृतिक पर्यटन संभावनाओं के द्वार खोलती एक विरासत

पातोला महादेव

अभिषेक श्रीवास्तव
सहायक आचार्य, भूगोल,
संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा

मानव मन की जिज्ञासा व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है जो उसे भ्रमण-विचरण हेतु प्रेरित करती है। इस प्रेरणा से कोई व्यक्ति विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है और नए-नए तथ्यों को संकलित कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, यही पर्यटन है। भीलवाड़ा शहर के निकट पुर कस्बे में भौगोलिक विरासत और ज्ञान को प्रत्यक्ष करता एक ऐसा ही नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण और भौगोलिक परिघटनाओं को दर्शाता पर्यटन स्थल है ''पातोला महादेव''।

पातोला महादेव एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विरासत स्थल है। धरातल से काफी गहराई में स्थित होने के कारण स्थानीय स्तर पर इसे ''पातोला महादेव'' कहा जाने लगा। प्राकृतिक सौंदर्य व भौगोलिक संरचना की विविधता से परिपूर्ण इस रमणीक स्थल को प्रकृति ने भिन्न-भिन्न प्रकार के मन-भावन सुंदर जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों व शैल संरचनाओं से सुसज्जित किया है।

पातोला महादेव भीलवाड़ा जिले के पुर कस्बे में $25^0 19'$ उत्तरी अक्षांश तथा $74^0 33'$ पूर्वी देशांतर के मिलन बिन्दु पर स्थित है। लगभग 3 किलोमीटर लंबे सर्पिलाकार सड़क मार्ग के जरिए यह पुर कस्बे से सीधे जुड़ा हुआ है। कटोरेनुमा गर्त में स्थित पातोला महादेव अपनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहां भूमि से काफी नीचे अर्थात् ''पाताल'' स्थित एक गुहा में अति प्राचीन शिवालय है। इसी शिवालय के कारण इस स्थान को ''पातोला महादेव'' कहा जाने लगा। पातोला महादेव निकटवर्ती ग्रामवासियों के आराध्य देव हैं। यह चारों ओर हरी-भरी पहाड़ियों व वनस्पतियों से घिरा हुआ है।

प्राकृतिक सरोवर और जैव-विविधता (Natural Pond and Biodiversity)

गुहा मंदिर में स्थित शिवालय के ठीक सामने स्थित प्राकृतिक सरोवर का मनोरम दृश्य वर्षा ऋतु में देखते ही बनता है, जब यह जल से लबालब भरा होता है। आसपास के गांवों के बच्चे यहां जलक्रीड़ा का आनन्द लेने आया करते हैं। सरोवर का जल पवित्र माना जाता है जिसके इर्द-गिर्द धार्मिक अनुष्ठान व विभिन्न परंपरागत कर्म काण्डों का आयोजन किया जाता है। इस सरोवर का जल पेयजल व सिंचाई का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

पातोला महादेव में सरोवर तथा उसके चारों ओर जीवन की अद्भुत विविधता दिखाई देती है। एक छोटे से परिसर में इतनी प्रचुर जैव-विविधता विरले ही मिलती है।

गार्नेट भंडार (Garnet Deposits)

पातोला महादेव परिसर में ''पुर-बनेड़ा आग्नेय शैल समूह'' की शिलाओं का विशाल भंडार मौजूद है जिनमें ''गार्नेट'' पाया जाता है। गार्नेट आभूषणों में प्रयुक्त किया जाने वाला एक मूल्यवान पत्थर है जो कि लाल रंग का होने के कारण ''रक्तमणि'' कहलाता है। इसे ''तामड़ा'' भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसे अंगूठी में नग के

यारडंग

रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभ्रक की प्रचुरता के कारण यहां की शिलाएं चांदी की सी चमकती प्रतीत होती हैं, जिनमें जड़ित गार्नेट इनकी खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देता है।

मरु वार्निश (Desert Varnish)

पातोला महादेव में पाई जाने वाली शिलाओं की सतह पर अपक्षय (टूट-फूट) के कारण लौह ऑक्साइड तथा सिलिका की लाल व भूरे रंग की कोटिंग देखी जा सकती है जिसे ''मरु वार्निश'' कहते हैं। मरु वार्निश सामान्यत: किसी भी महीने में देखी जा सकती है किन्तु वर्षाकाल के उपरान्त शीतकाल के आगमन के साथ ही इसे अधिकता में देखा जा सकता है। शीतकाल अपक्षयन गतिविधि के लिए सबसे आदर्श समय होता है।

क्षिप्रिका (Rapids)

जब कोमल और कठोर शैलें अनुप्रस्थ(क्षैतिज) दिशा में स्थित होती हैं तब जल जनित अपरदन के कारण कोमल शैलें शीघ्र ही अपरदित हो जाती हैं। प्रवाहित वर्षा जल के ढाल पर ''एक सोपानाकार संरचना'' या सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे क्षिप्रिका कहते हैं। यह क्षिप्रिका प्राकृतिक सीढ़ियों जैसी ही दिखाई देती है जिनका प्रयोग यहां पर्यटकों द्वारा यारडंग तक पहुंचने के लिए किया जाता है।

ट्रैकिंग (Trekking)

यहां की ऊंची-नीची पहाड़ियां रोमांच पसंद लोगों के लिए माउंटेन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। प्राय: युवाओं को यहां ट्रैकिंग करते देखा जा सकता है।

गार्नेट भण्डार

मरु वार्निश

क्षिप्रिका

श्री गंगानगर के किन्नू की सुगन्ध से महकेगा बांग्लादेश

368 मीट्रिक टन किन्नू लेकर बांग्लादेश पहुंची रेलगाड़ी

अनिल कुमार शाक्य
जनसम्पर्क अधिकारी, गंगानगर

श्रीगंगानगर के किन्नू की महक कई देशों से होती हुई अब बांग्लादेश तक भी पहुंच गई है। 30 दिसंबर 2021 को श्रीगंगानगर से करीब 368 मीट्रिक टन किन्नू लेकर स्पेशल रेलगाड़ी बांग्लादेश के बनगांव के लिए रवाना हुई। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किन्नू के परिवहन के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाई गई है। इस उपलब्धि पर गंगानगर के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय किन्नू क्लब के पदाधिकारी भी बेहद उत्साहित हैं। किन्नू स्पेशल की रेलगाड़ी की रवानगी पर उत्साहित पदाधिकारियों ने बाकायदा किन्नू जैली से बना केक भी काटा। इस रेलगाड़ी की सफलता के बाद किन्नू के साथ-साथ अन्य कृषि जिंसों की रवानगी के लिए भी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

जब बांग्लादेश तक गंगानगर से किन्नू भेजने के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाने की बात चली तो यह काम मुश्किल नजर आया लेकिन अब यह प्रयास सफल हो चुका है। बांग्लादेश में गंगानगरी किन्नू पहुंचने से न केवल गंगानगर का देश-दुनिया में नाम होगा

बल्कि स्थानीय किन्नू की मिठास भी गंगानगर से निकल कर दूसरे मुल्कों के लोगों तक समय पर पहुंच सकेगी।

किन्नू के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलाए जाने पर जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने इसे गंगानगर जैसे कृषि प्रधान जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि किन्नू के लिए विशेष रूप से स्पेशल रेलगाड़ी चलाने से जिले और प्रदेश का गौरव बढ़ेगा और किन्नू उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। इसका फायदा किन्नू उत्पादकों के साथ-साथ बांग्लादेशवासियों को भी मिलेगा।

15 बोगी की स्पेशल रेलगाड़ी

जिस स्पेशल रेलगाड़ी को श्री गंगानगर से बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया, वह अपने साथ 368 मीट्रिक टन किन्नू लेकर गई। खरीद, ग्रेडिंग और वैक्सिंग के बाद गंगानगर में 32 रुपए प्रतिकिलो की दर से बिकने वाला किन्नू बांग्लादेश में 104 से लेकर 108 रुपये प्रति किलो थोक के भाव से बिकेगा। अभी तक गंगानगर से बांग्लादेश तक किन्नू ट्रकों के जरिए भेजा जाता रहा है। रेलगाड़ी से बांग्लादेश किन्नू भेजने पर रेलवे 24 टन का किराया लगभग 1 लाख 10 हजार रुपए वसूलेगी।

सब्सिडी के रूप में किराया राशि की 50 प्रतिशत राशि व्यापारियों को वापस मिलेगी। इस लिहाज से बनगांव तक 24 टन का किराया तकरीबन 55 हजार रुपये रहेगा। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर पर 39 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी भी देनी होगी। व्यापारिक नजरिए से देखें तो गंगानगर में प्रति किलो की दर से बिकने वाला किन्नू बांग्लादेश में कैरेट की दर से बिकेगा। गंगानगर में किन्नू के व्यापारी बाबू खान रिजवी बताते हैं कि बांग्लादेश में किन्नू कैरेट की दर से बिकता है। एक कैरेट में 24 किलो किन्नू आते हैं, जो 2500 से 2600 रुपए (थोक में 104 से 108 और रिटेल में 125 से 130 रुपए प्रतिकिलो) में बिकते हैं। किन्नू के बांग्लादेश पहुंचने के बाद उम्मीद है कि गंगानगर से अन्य कृषि उत्पाद भी दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकेंगे, जैसे गंगानगर की गाजर भी रेलगाड़ी के जरिए अन्य राज्यों में भेजी जा सकेगी।

पांच दिन के बजाय दो दिन में पहुंचा गंतव्य

गंगानगर से स्पेशल रेलगाड़ी के जरिए 40 से 45 घंटे बाद बनगांव पहुंचा गंगानगर का किन्नू पहले की अपेक्षाकृत ताजा रहा। ट्रक के जरिए पहले बांग्लादेश तक गंगानगरी किन्नू पहुंचने में 5 दिन लगते थे, लेकिन अब 45 घंटे में सफर तय होने से बांग्लादेश वासियों को ताजा किन्नू मिल सकेंगे।

किन्नू की खेती के लिए जगप्रसिद्ध है गंगानगर

किन्नू के उत्पादन से लेकर कारोबार तक में गंगानगर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अपनी चमक, रंग और मिठास के लिए प्रसिद्ध गंगानगरी किन्नू की जिले में 11,174 हैक्टेयर में बागवानी होती है। उद्यान विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती प्रीतिबाला गर्ग बताती हैं कि 11,174 हैक्टेयर में लगे किन्नू के बागों से इस सीजन में 1,80,000 टन उत्पादन होने की उम्मीद है। गंगानगर की मिट्टी, पानी और तासीर में उपजने वाला किन्नू देशभर के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया तक बिकने जाता है। अच्छी मांग होने की वजह से जिले में किन्नू के बागों के अलावा इसकी ग्रेडिंग और वैक्सिंग की दर्जन भर इकाइयां लगी हुई हैं।

गंगानगर जिले के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में भी किन्नू की बेहतरी और उसकी प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे किन्नू क्लब गंगानगर के अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन भी इस पहल के लिए राज्य सरकार को साधुवाद देते हुए कहते हैं, ''किन्नू की बागवानी और इसके कारोबार से जुड़े सभी लोगों के लिए यह अच्छी शुरुआत है।'' इससे न सिर्फ किन्नू की दूसरे देशों में पहुंच सुगम होगी बल्कि गंगानगर में भी किन्नू के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

हरी झंडी दिखाकर किन्नू स्पेशल रेलगाड़ी रवाना करते हुए जनप्रतिनिधियों, जिला कलक्टर और किन्नू व्यापारियों सहित रेलवे के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि किन्नू के लिए विशेष रूप से चलाई गई स्पेशल रेलगाड़ी का ये सिलसिला इसी तरह बना रहेगा। ●

गुणकारी है किन्नू

● अन्य खट्टे फलों की तुलना में किन्नू में लगभग 2.5 गुना अधिक कैल्शियम होता है। नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। ● किन्नू के सूखे छिलके का उपयोग विभिन्न हर्बल कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है। इससे ब्लैकहेड्स का प्रभावी घरेलू उपचार किया जाता है। ● इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व कैंसर से लड़ने में सहायता करते हैं। ● किन्नू का सेवन आंतों को मजबूत बनाता है और पुरानी कब्ज को दूर करता है। ● रोज़ाना किन्नू खाने से किडनी स्टोन की समस्या में राहत मिलती है और इसकी आशंका भी खत्म होती है। ● भरपूर मात्रा में विटामिन सी के कारण शरीर में उचित मात्रा में आयरन रहता है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो हाई और लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद पोटेशियम के कारण हृदय रोग नहीं होते हैं।

प्रदेशवासियों के नाम पोस्टकार्ड

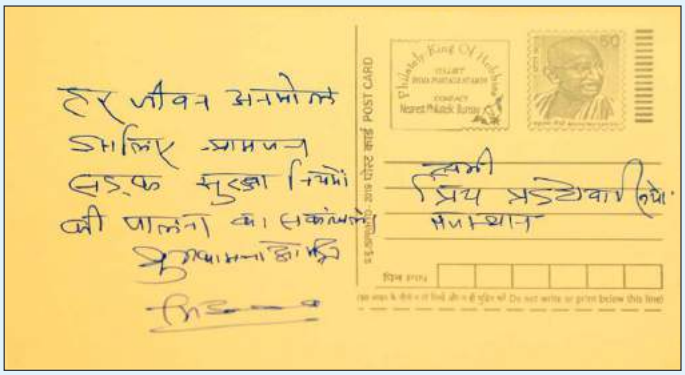

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पोस्टकार्ड पर प्रदेशवासियों के नाम सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने का संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल, इसलिए आमजन सड़क सुरक्षा नियमों की पालना का संकल्प ले। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल के अवलोकन के दौरान पोस्टकार्ड पर यह भावना लिखी। साथ ही व्हीकल सिमुलेटर पर स्वयं ड्राइविंग कर लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जानकारी ली। ई-चालान, सीपीआर तकनीक, प्राथमिक उपचार प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के अभिनव प्रयास

- सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने, जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपये और प्रशस्ति पत्र के लिए 'मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना' लागू।
- प्रथम राज्य के रूप में राजस्थान ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में अंगदान के डिक्लरेशन (हां या ना) को अनिवार्य किया। इस अभिनव पहल में 01 सितंबर 2020 से 12 जनवरी 2022 तक 2.25 लाख से अधिक स्थाई लाइसेंसधारक अंगदान की सहमति देकर अपने लाइसेंस पर 'हार्ट विद ऑर्गन डोनर' का लोगो अंकित करा चुके हैं।
- इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस एप पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की ऑनलाइन रजिस्ट्री कर उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर कारणों का अध्ययन किया जा रहा है।
- हर जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापना और प्रदेश के 37 परिवहन जिलों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक की स्थापना की जा रही है।
- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में सड़क सुरक्षा फंड से बनी स्किल लैब में चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों सहित आमजन को बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रदेश की 65883 राजकीय स्कूलों में सड़क सुरक्षा पुस्तकें वितरित की गई है।
- सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के तीन जिलों को 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा अवार्ड' दिया जायेगा।
- प्रदेश की एंबुलेंसों में व्हीकल लाइव लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम स्थापित कराए जा रहे हैं।

सुरेन्द्र बगवाड़ा
जनसम्पर्क अधिकारी

ग्रामीणों से मिलकर लिया फीडबैक

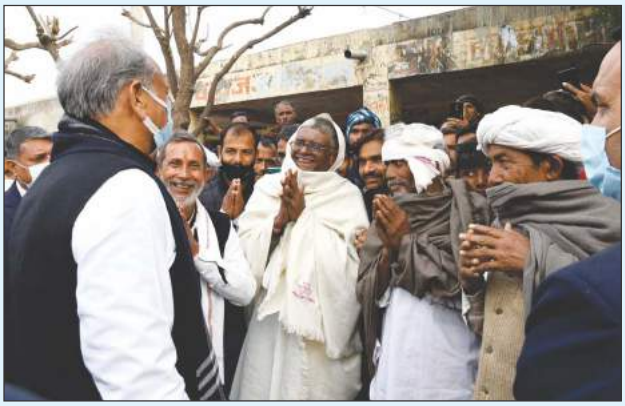

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बाड़ा पदमपुरा तथा शिवदासपुरा, जयपुर के ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि राज्य सरकार ने लोगों को बीमारियों के उपचार के खर्च से चिंतामुक्त करने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। सभी लोग इस योजना में पंजीयन कराएं और जो लोग किसी कारण से इस योजना में अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें।

इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी है। निःशुल्क उपचार होने के कारण क्षेत्र में करीब-करीब सभी लोग इससे जुड़ चुके हैं। आमजन को इससे इलाज में काफी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वे लोग मास्क पहनने तथा वैक्सीनेशन लगाने में कोई ढ़िलाई नहीं बरतें।

जालोर का 287 स्तम्भों और 159 गुम्बदों वाला तोपखाना

अविनाश चौहान
सहा. प्रशा. अधि. सूजसका, जालोर

शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही ऐतिहासिक जालोर नगरी में परमार राजा भोज ने अपने शासनकाल में आठवीं शताब्दी के मध्य एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। राठौड़ शासनकाल में इस स्थान पर तोपें रखे जाने के कारण इसे तोपखाना के नाम से जाना जाता है। तोपखाना शहर के मध्य छोटे बड़े 287 स्तम्भों और 159 गुम्बदों वाला ''समचौरस'' स्मारक है। यह स्मारक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है जो कि लगभग 200 फीट लम्बा व चौड़ा है। इसके चारों और ऊंची दीवार बनी हुई है तथा प्रवेश के लिए मध्य में लगभग 20 फीट का बड़ा और मजबूत दरवाजा बना हुआ है।

स्मारक के अन्दर गुम्बदों के नीचे एक विशाल हॉल बना हुआ है। जिसके दोनों ओर लगभग 60-60 स्तम्भों के बरामदे बने हुये हैं। जालोर शहर के मध्य छोटे-संकरे रास्तों से होते हुए यहां तक पहुंचा जाता है। प्रतिवर्ष आयोजित जालोर महोत्सव के दौरान देशी-विदेशी पर्यटकों को इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू करवाने के लिये यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

I M Shakti

सपनों की 'उड़ान' के लिए नारी के स्वाभिमान के लिए

नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना

माहवारी कोई बीमारी नहीं है, न ही ये कोई शर्म और संकोच का विषय है। समाज को अब सोच बदलनी पड़ेगी, हमें महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। महिलाओं की गरिमा, सम्मान और निजता की दिशा में एक जरूरी कदम है **"उड़ान"**

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

सुश्री अवनी लेखरा
(अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी)

क्यों ज़रूरी है सेनेटरी नैपकिन

- देश में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लड़कियों को माहवारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है।
- एक अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 62% महिलाएं पीरियड्स के समय सेनेटरी नैपकिन की जगह कपड़े का प्रयोग करती हैं। पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल की गई अनहाइजिनिक (अस्वच्छ) वस्तुओं से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है।
- जानकारी के अभाव में लड़कियों को माहवारी संभालने में मुश्किलें आती हैं और उनके लिए शारीरिक व मानसिक बीमारियाँ खड़ी होती हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं होती, आत्मविश्वास डगमगाता है और खुद की नज़रों में कमतर महसूस करने लगती हैं।
- सब महिलाओं को माहवारी के समय पैड का उपयोग करना जरूरी है, माहवारी प्रकृति का उपहार है, यह कोई शर्म की बात नहीं है।
- सेनेटरी नैपकिन या पैड की जगह अन्य कपड़े अथवा चीजों के इस्तेमाल से बांझपन (इनफर्टिलिटी) तक हो सकता है।

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक–श्रीमती अलका सक्सेना मै.कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60 लागत मूल्य 30.56 रुपए • 5,00,000 प्रतियां